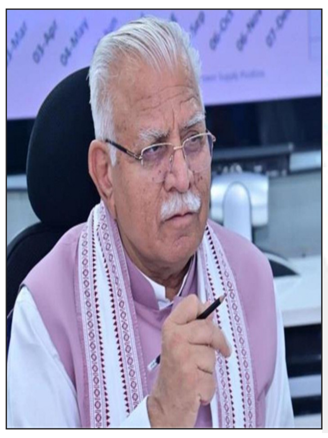

सब का सपना

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

अब बदलेगा शहरी नक्शा : छोटे शहर बनेंगे .. पेज: 6

साउथ मे मिले प्यार पर अभिनेत्री तमन्ना... पेज: 8

वर्ष : 02 | अंक : 15 | गुरूवार 16 अप्रैल 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2 रुपए

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट की जमानत पर लगी रोक

असम सरकार की अपील पर सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा है।

दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विस्व सरमा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने रिनीकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, इस फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि पवन खेड़ा असम के सक्षम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब कथित अपराध गुवाहाटी में हुआ, तो तेलंगाना हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कैसे बनता है।

इसके साथ ही आधार कार्ड से जुड़े एक पहलू पर भी बहस हुई। अदालत को बताया गया कि याचिका दाखिल करते समय पवन खेड़ा की ओर से उनकी पत्नी का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था, ताकि तेलंगाना से संबंध दिखाया जा सके। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताते हुए इसे कानून का दुरुपयोग बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अधिकार क्षेत्र का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई।

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और मामले में नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में मामला दर्ज किया है। 7 अप्रैल को पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली स्थित आवास भी पहुंची थी। इसके बाद खेड़ा ने 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें अस्थायी राहत मिली थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हो गई है।

लखीमपुर खीरी में अम्बेडकर की मूर्ति खंडित होने पर बवाल, भीड़ ने की पत्थरबाजी

-20 पुलिसकर्मी घायल, कई गाड़ियों को फूंका, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

लखीमपुर खीरी (एजेंसी)। लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांकेगंज कस्बे में मंगलवार को अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मूर्ति रखने की कोशिश में आयोजकों और अन्य लोगों में झड़प हुई, जिससे मूर्ति गिरकर खंडित हो गई। आक्रोशित भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पत्थर बरसाए और कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने लाठीचार्ज किया। घटना में 20 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय पत्रकार घायल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांकेगंज कस्बे की एक सरकारी भूमि पर मूर्ति स्थापना को लेकर लंबे समय से विवाद था। सहमति बनी थी कि केवल बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण होगा, लेकिन कुछ लोग चुपके से मूर्ति ले आए। एक चश्मदीद महिला के मुताबिक कुछ लोगों ने जबरन मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की, जिसका विरोध होने पर मारपीट शुरू हो गई। इस खींचतान के दौरान मूर्ति गिरकर खंडित हो गई, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही जब पुलिस बल मौके पर पहुंची, तो अराजक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने न केवल मारपीट की, बल्कि पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को बचाव में हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पत्थरबाजी में कई जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने खंडित मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया ताकि माहौल और न बिगड़े। मामले की गंभीरता देखते हुए डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ बांकेगंज पहुंचीं। इलाके में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शांति व्यवस्था बनी हुई है।

आंध्र प्रदेश में सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं डिस्ट्रिक्ट से बुधवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां रसोई गैस सिलेंडर फटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। धमाका इतना भीषण था कि इसकी चपेट में आकर दो रिहायशी मकान पूरी तरह ढह गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना जिले के कादिरआई मंडल के कामरावारीपल्ली गांव में दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। पुलिस अधीक्षक एस सतीश ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस घर में विस्फोट हुआ, वहां तेलंगाना के प्रवासी मजदूर रह रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण यह विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। धमाके के कारण आसपास तेज कंपन हुआ और दो मकान जमींदोज हो गए। मलबे में दबने और आग की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में मदद की। हालांकि, विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पीड़ितों को बचाया नहीं जा सका। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा बर्फानी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु

जालंधर (एजेंसी)। लाखों शिव भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन सुबह से विभिन्न बैंकों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दी। अनुमान है कि इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होगा। इस देखकर प्रशासन सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं। बात दें कि पहलगाम रास्ते में चढ़ाई अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन समय अधिक लगता है, जिसकी दूरी करीब 46 किमी है। जबकि बालटाल वाला रास्ता छोटा है, करीब 14 किमी है, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी कठिन मानी जाती है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं। भक्त श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फोटो और हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं ऑफलाइन के लिए देशभर की अधिकृत बैंक शाखाओं में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यहाँ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर परमिट जारी किए जाते हैं। प्रति व्यक्ति पंजीकरण शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। यात्रा की दुर्गमता को देखकर श्राइन बोर्ड ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं, यात्रियों के पास 8 अप्रैल 2026 के बाद अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीएचसी) होना चाहिए। केवल 13 से 70 वर्ष की आयु के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दो लोगों की मौत

हरदोई (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के हरदोई जिले के जलालपुर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से बीमार हो गया। जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधान विद्यावती के पति सुरेंद्र अपने घर में बने सीमेंट के टैंक को गेहूं भंडारण के लिए साफ करवा रहे थे। इस टैंक में पहले तिरपाल बिछाकर उसके ऊपर भूसा डाला गया था, जिससे अंदर जहरीली गैस बन गई थी। सफाई के दौरान गांव के कैलाश सबसे पहले टैंक में उतरे, लेकिन अंदर पहुंचते ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वे बेहोश हो गए। कैलाश को बचाने के लिए सुरेंद्र तुरंत टैंक में उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आकर अचेत हो गए। इसके बाद तीसरे युवक प्रमोद को रस्सी के सहारे नीचे भेजा गया, मगर वह भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाकर रस्सी की मदद से प्रमोद को बाहर निकाला और किसी तरह अन्य दोनों को भी बाहर निकाला। तीनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र और कैलाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रमोद का इलाज जारी है। इस घटना ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है और जहरीली गैस से जुड़े खतरों के प्रति सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया है।

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, छह की मौत और 15 घायल

फतेहगढ़ साहिब(एजेंसी)। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में बैसाखी मेला देखकर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 15 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फतेहगढ़ साहिब क्षेत्र से करीब 40 श्रद्धालुओं का एक जत्था बैसाखी के पावन पर्व पर श्री आनंदपुर साहिब में मत्था टेकने और मेले में शामिल होने गया था। देर रात जब सभी लोग बस से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, चलती बस में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू हुई बस सड़क किनारे लगे बिजली के एक खंभे से जा टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और भीतर चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से घायलों को मोरिंडा और फतेहगढ़ साहिब के सरकारी अस्पतालों में भिजवाया। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए बड़े केंद्रों में रेफर किए जाने की खबर है। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क के बीच से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद से प्रभावित गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

पुलिस ने नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने वाले को दबोचा

-आरोपी लड़कियों को ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेलने मुंबई-पुणे ले जाता था

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने 180 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण और उनके 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को 'लव ट्रैप' में फंसाकर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाता था, जहां उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाता था। इन वीडियो का इस्तेमाल वह लड़कियों को ब्लैकमेल करने और देह व्यापार में धकेलने के लिए करता था। आशंका है कि इनमें से कुछ वीडियो शेयर भी किए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अयाज उर्फ तनवीर के रूप में हुई है, जो परतवाड़ा शहर का रहने वाला है. वॉट्सएप और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। इस मामले की शिकायत बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने एसपी (ग्रामीण) को ज्ञापन सौंपकर की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि इस मामले में एसआईटी का गठन नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों से पूरे समुदाय की छवि खराब होती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयाज पहले एआईएमआईएम से जुड़ा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने ये वीडियो किसी और के साथ शेयर किए थे, या वह किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था।

रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि सामाजिक बदनामी के डर से अब तक किसी भी पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एसपी ने पीड़ितों के परिवारों से आगे आने की अपील की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, इसके अलावा, राज्य सरकार उनकी कानूनी और काउंसलिंग सेवाओं का भी ध्यान रखेगी। अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में मंदिर पक्ष का तक... धर्म की प्रथा उस समुदाय की आस्था से तय होती, न कि न्यायिक मानकों से

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान धार्मिक अधिकारों और संवैधानिक सीमाओं पर अहम बहस हुई। सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थनम बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि शीर्ष अदालत को धार्मिक मान्यताओं की सही-गलत की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार, किसी भी धर्म की प्रथा उस समुदाय की आस्था से तय होती है, न कि न्यायिक मानकों से होती है।

वकील सिंघवी ने कहा कि धर्म मूल रूप से एक सामूहिक विश्वास है, इसलिए कुछ व्यक्तियों के अधिकार पूरे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हावी नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक अधिकारों पर रोक केवल विधि (कानून) के माध्यम से ही लग सकती है, न कि केवल सरकारी आदेशों या निर्देशों से रोक लगा सकते है। यदि बिना कानून के हस्तक्षेप हुआ, तब इससे सरकार को मनमाने ढंग से धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देने का मौका मिल सकता है।

इस मामले की पृष्ठभूमि में केरल हाईकोर्ट का 1991 का फैसला है, इसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस

प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताकर हटा दिया। इसके बाद पुनर्विचार याचिकाओं के आधार पर कई संवैधानिक प्रश्नों पर अब विस्तृत बहस हो रही है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने कहा कि यदि सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, तब अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि अलग-अलग जातियों को अलग स्थानों पर बैठाकर भोजन कराना असमानता का प्रतीक है। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि कुछ धार्मिक प्रथाएं ऐसी हो सकती हैं, जिसमें दर्शन या पूजा के तरीके अलग हों, और हर स्थिति में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने तर्क दिया कि अदालत धार्मिक प्रथाओं को अपनी व्याख्या के आधार पर बदल नहीं सकती, यदि वे किसी धर्म का स्थापित और मान्य हिस्सा हैं। हालांकि, यदि कोई प्रथा कानून के विरुद्ध हो या पूरे समुदाय द्वारा मान्य न हो, तब उस पर रोक लग सकती है।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश ने सवाल उठाया कि सामाजिक सुधार से जुड़े कानून, जैसे हिंदू उत्तराधिकार कानून, किस आधार पर बनाए गए। वहीं, आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान लागू होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। इस पर मंदिर के वकील सिंघवी ने चेतावनी दी कि यदि अदालतें यह तय करने लगें कि कौन-सी धार्मिक प्रथा आवश्यक है और कौन-सी नहीं, तब न्यायपालिका धर्म के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगेगी, जिसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जैन दिगंबर साधुओं की परंपरा का उल्लेख किया, जो सामान्य सामाजिक दृष्टि से अलग हो सकती है, लेकिन उनके धर्म का अभिन्न हिस्सा है। अंत में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि इस मामले में ÷संवैधानिक नैतिकता÷ के बजाय ÷सार्वजनिक नैतिकता÷ का पहलू भी महत्वपूर्ण रहेगा। यह पूरा मामला धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और न्यायिक सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाता है।

सत्ता को ठोकर मारकर सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना हर किसी के बस की बात नहीं

-जेडीयू नेता बोले-यह साहस, चरित्र, त्याग सिर्फ नीतीश जैसे नेता ही दिखा सकते हैं

पटना (एजेंसी)। बिहार में बुधवार को बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था। इधर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता को ठोकर मारकर सिद्धान्तों को सर्वोपरि रखा। जेडीयू के विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट के जरिये नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है।

उन्होंने एक्स पर सवाल यह नहीं कि आपने क्या त्याग किया, सवाल यह है कि आपके इस त्याग की चर्चा कौन करे शीर्षक के जरिए नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लिखा, कोई एक दिन के लिए भी त्याग नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी त्याग कर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो राजनीति के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती हैं। उन्होंने लिखा सत्ता को ठोकर मारकर सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना हर किसी के बस की बात नहीं।

यह साहस, यह चरित्र, यह त्याग- सिर्फ नीतीश कुमार जैसे नेता ही दिखा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वह दौर- जब 118 नरसंहारों की गूंज थी, जब चरवाहा विद्यालय जैसे प्रयोगों ने शिक्षा का मजाक बना दिया था, जब समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता की राजनीति की जाती थी, जब गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को जानबूझकर विकास से दूर रखा गया। नीरज ने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अंधकारमय समय में, नीतीश कुमार ने सिर्फ सरकार नहीं चलाई- उन्होंने व्यवस्था बदली, सोच बदली, समाज को नई दिशा दी। यह वही नेता हैं जिन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में अपनी भूमिका निभाई और बिहार लौटकर विकास की नई परिभाषा गढ़ी।

उन्होंने कहा कि सांसद या विधायक बन जाना बड़ी उपलब्धि नहीं है- लेकिन सामाजिक जकड़नों को तोड़ना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए रोडमैप बनाना और उसे जमीन पर उतारना, यह असाधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति ही कर सकता है। नीरज कुमार ने विश्वास जताते हुए कहा कि यही कारण है कि सात निश्चय केवल योजना नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का विजन है। सवाल उठाने वालों को लेकर कहा कि आज जो लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें इतिहास के आईने में खुद को देखना चाहिए। क्योंकि फर्क साफ है- एक तरफ सत्ता के लिए समाज को बांटने की राजनीति और दूसरी तरफ समाज को जोड़ने की कार्यनीति। आपका योगदान महान है, लेकिन आपका त्याग- उससे भी बड़ा है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को करेंगे निकाल बाहर : घोष

अराजकता और उग्र प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं

खड़गपुर (एजेंसी)। पंश्चित बंगाल चुनाव में बीजेपी नेता और खड़गपुर से उम्मीदवार दिलीप घोष ने सम्राट चौधरी और पीएम मोदी द्वारा बंगाल के लिए घोषित छह गारंटियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार एनडीए विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी के चुने जाने पर घोष ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी कदम दर कदम आगे बढ़ रही है और लोग उसे वोट दे रहे हैं। बीजेपी सुशासन प्रदान करती है। अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श करके निर्णय लेती है।

इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (आई-पैक) के निदेशक विनेश चंदेल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि आई-पैक से जुड़े घोटालों के कई आरोप हैं। कई शिकायतें पहले ही सामने आ चुकी हैं। जांच जारी है और जैसे-जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। ऐसी जांचों के निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की जाती हैं और जेल भेजा जाता है। घोष ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत अहम हैं। पीएम मोदी खुद नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को शरण दी है। बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा।

इसके पहले मंगलवार को दिलीप घोष ने कहा था कि कोयला, बालू से लेकर गो-तस्करी तक पश्चिम बंगाल में यह एक बड़ी समस्या है। तस्करी के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। हिंसा जैसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे भी यही पैसा होता है। ऐसे मामलों में जो भी दोषी है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार की घटनाएं आज भी लोगों को याद हैं। टीएमसी के गुंडों ने लोगों को अभी से डराना शुरू कर दिया है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

तेल कंपनियों को हो रहा नुकसान... क्या चुनाव के बाद लोगों को लग सकता बढ़ी कीमत का झटका

नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल 125 रुपये प्रति लीटर जा सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा झटका लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि देश में बीते चार वर्षों से ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसका भारी वित्तीय दबाव सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) अप्रैल 2022 से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं। जबकि भारत में ईंधन मूल्य निर्धारण को एक दशक पहले ही सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर बाजार आधारित कर दिया गया था, इसके बावजूद इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाईं।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थीं, फिर कुछ समय के लिए गिरकर लगभग 70 डॉलर तक आईं, और हाल ही में अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद फिर से करीब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इस अस्थिरता का

सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों की लागत पर पड़ा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। वैश्विक वित्तीय संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि कच्चे तेल की कीमत 135 से 165 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहती है, तब यह नुकसान और बढ़ सकता है। साथ ही, हर 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से प्रति लीटर करीब 6 रुपये का अतिरिक्त घाटा जुड़ जाता है।

वित्तीय नुकसान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने ये कंपनियां रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही थीं। हालांकि मोदी सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद यह घाटा घटकर करीब 1,600 करोड़ रुपये प्रतिदिन बचा है। लेकिन यह राहत आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची, बल्कि कंपनियों के घाटे को कम करने में इस्तेमाल हुई। यदि कंपनियां अपने इस नुकसान की भरपाई करना चाहें, तब पेट्रोल की कीमतें 125 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा सकती हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव के बाद उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

चुनाव बाद लग सकता है झटका

सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव के बाद ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि के आसार हैं। भारत ने साल 2025 में अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 फीसदी आयात किया और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति वह अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

नारी-आरक्षणः नये भारत का आधार एवं संभावनाओं का शिखर

ललित गर्ग

नया भारत जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, उसमें नारी शक्ति की भूमिका केंद्रीय है। आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। विज्ञान, तकनीक, खेल, शिक्षा, प्रशासन और उद्यमिता-हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां यह प्रमाणित करती हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारत की राजनीति और समाज में जो नई चेतना उभरकर सामने आई है, वह केवल एक विधायी परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक रूपांतरण एवं नये भारत-निर्माण की संभावनाओं की प्रस्तावना है। निश्चिततौर पर भारत अब अपने विकास की धुरी में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी को अनिवार्य मानने लगा है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण का मुद्दा केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय समाज की उस अंतधार्रा से जुड़ा रहा है, जिसमें बराबरी, सम्मान और अवसर की मांग निरंतर उठती रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह सही कहा कि यह इस सदी के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। पहले यह अधिनियम नई जनगणना के बाद लागू होना था, पर उसमें देरी के चलते सरकार ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का निर्णय किया। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है, पर इस आपत्ति को महत्व देने से अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ताजा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनने वाले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगता और तब तक 2029 के आम चुनाव हो जाते। इसी कारण इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। चूंकि यह सत्र विधानसभा चुनावों के बीच बुलाया जा रहा है, इसलिए भी कई विपक्षी दलों को यह कांटों की तरह चुभन दे रहा है।

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास विरोधाभासों से भरा रहा है। एक ओर देश ने इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला नेतृत्व को देखा, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक सीमित बनी रही। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत के आसपास है, जो यह बताती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर अभी भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण अधिनियम उस अंतर को पाटने का एक संगठित और संरचनात्मक प्रयास है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में जनगणना और परिसीमन को लेकर जो विवाद सामने आया है, वह भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को भी उजागर करता है। सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करने का निर्णय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दशार्ता है, क्योंकि नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया में होने वाली देरी महिला आरक्षण को वर्षों तक टाल सकती थी। विपक्ष की आशंकाएं अपनी जगह पर हैं, परंतु अभी तक उनके समर्थन में ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं।

भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े निर्णय को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा रही है और महिला आरक्षण भी इससे अछूता नहीं है। विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाना कि सरकार इस पहल के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र में लिए जाने वाले अधिकांश निर्णयों के पीछे राजनीतिक गणित काम करता है। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ है या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर कितना सकारात्मक पड़ता है। यदि महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और नीति निर्माण में उनका दृष्टिकोण शामिल होता है, तो यह संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे एक निर्णायक मतदाता वर्ग के रूप में उभरी हैं। 2019 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही और कई राज्यों में उन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह परिवर्तन केवल संख्या का नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। महिलाएं अब अपने अधिकारों और हितों के प्रति अधिक सजग हो रही हैं और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

सरकारी योजनाओं ने भी इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस की उपलब्धता, जनधन योजना के तहत बैंकिंग सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और मातृत्व लाभ योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार किया है। इन योजनाओं का प्रभाव केवल आर्थिक या भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी रहा है, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय हुई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को इस संदर्भ में विशेष रूप से स्मरण किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करते हुए महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका यह विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। आज जब महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो यह उसी विचारधारा का विस्तार प्रतीत होता है, जिसमें महिलाओं को केवल संरक्षण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का अवसर प्रदान किया जाता है।

हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण अपने आप में कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह एक आवश्यक कदम है, परंतु पर्याप्त नहीं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने से महिलाओं की आवाज अवश्य मजबूत होगी, परंतु सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। आज भी भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, परंतु उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण के क्रियान्वयन के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि कई स्थानों पर महिलाएं केवल नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाएंगी और वास्तविक निर्णय उनके पुरुष परिजन लेंगे। पंचायत स्तर पर इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं, परंतु समय के साथ महिलाओं ने इस स्थिति को बदला भी है और अपने अधिकारों को स्वयं संभालने की क्षमता विकसित की है। इसी प्रकार राजनीतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है, ताकि महिलाएं केवल प्रतिनिधि न होकर प्रभावी नीति निमार्ता बन सकें। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन आवश्यक है। यदि दल अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं देंगे, तो केवल आरक्षण के माध्यम से वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। दलों को चाहिए कि वे महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करें, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।

नया भारत जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, उसमें नारी शक्ति की भूमिका केंद्रीय है। आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। विज्ञान, तकनीक, खेल, शिक्षा, प्रशासन और उद्यमिता-हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां यह प्रमाणित करती हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। इसरो की महिला वैज्ञानिकों की सफलता, ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का प्रदर्शन, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के उदाहरण इस परिवर्तन के सशक्त प्रमाण हैं। इस अधिनियम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि विकास का कोई भी मॉडल तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें आधी आबादी की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो। हालांकि इसके क्रियान्वयन में राजनीतिक मतभेद और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती रहेंगी, परंतु इसकी मूल भावना पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के अवसर के रूप में देखा जाए। यदि सरकार, विपक्ष और समाज मिलकर इस दिशा में कार्य करते हैं, तो यह अधिनियम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है। यही वह मार्ग है, जिस पर चलते हुए भारत एक सशक्त, समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और अधिक मजबूत कर सकता है।

संपादकीय

उम्मीदों का गलियारा

निस्संदेह, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के संरचनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के प्रवेश द्वार के बीच यात्रा के समय को छह घंटे से घटाकर ढाई घंटे करने का वायदा करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देगा। इंजीनियरिंग की विशिष्ट उपलब्धि से बढ़कर, परियोजना राजमार्गों की कल्पना में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। जो महज एक सड़क ही नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों, बाजारों और अवसरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा भी है। इस राजमार्ग के बनने से जहां परंपरागत मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से देहरादून और मसूरी आदि अन्य हिल स्टेशनों में पर्यटन बढ़ेगा। निस्संदेह, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिमी उ.प्र. के सहारनपुर व शामली जैसे जनपदों, जिन्हें विकास की दौड़ में पर्याप्त अवसर नहीं मिले, उनके लिये भी वरदान साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि खाद्यान्न, भंडारण और रियल एस्टेट में भी इस परियोजना के लाभ नजर आएंगे। कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत एकीकृत, उच्च गति वाले गलियारों के लिये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्यों को पूरा करता है। वहीं दूसरी ओर इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विकास और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। प्रतिष्ठित राजाजी पार्क क्षेत्र से गुजरने वाला यह ऊंचा वन्यजीव गलियारा, जिसमें वन्य जीवों के लिये अंडरपास बनाये गए हैं ताकि उनके प्राकृतिक आवागमन मार्गों में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। जो इस मान्यता की कसौटी पर खरा उतरता है कि विकास के बुनियादी ढांचे को प्रकृति के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में देश की विभिन्न बड़ी विकास योजनाओं वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों और मनुष्य के बीच जो संघर्ष बढ़ा है, वो विकास को पर्यावरण व वन्यजीवों के अधिवास के अनुकूल ढालने की जरूरत बताता है। कर्नाटक के हाथी गलियारे- जो बांदीपुर,नागरहोल और आसपास के जंगलों को जोड़ते हैं, दशार्ते हैं कि कि कैसे संपर्क मार्गों से वन्य जीवों के प्रवास-मार्ग की सुरक्षा होती है। जिससे मानव व वन्य जीवों का संघर्ष कम होता है। ऐसे में यदि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग में अभिनव प्रयास प्रभावी साबित होते हैं, तो यह नया एक्सप्रेसवे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भविष्य की परियोजना के लिए एक आदर्श साबित हो सकता है। हालांकि, इस राजमार्ग को लेकर कुछ चिंताएं अभी बाकी हैं। राजमार्ग को पूरा करने के दौरान अंतिम समय में निर्माण कार्यों में किए गए सुधार और इसमें पहले हुई कुछ देरी की रिपोर्टों से कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व समय सीमा के दबाव को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, किसी संरचना के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन उद्घाटन की समय सीमा से नहीं बल्कि उसकी मजबूती, सुरक्षा उपायों और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर ही होना चाहिए।

चिंतन-मनन

संयम से जीवन की उन्नति

कार्तिय माहात्म्य प्रवचनों में पं. रामनिवास ब्रजवासी जी ने कहा शरद ऋतु में की जाने वाली उपासनाओं से जहाँ चंद्र किरणों से प्राप्त होने वाले अमृत तत्व से देह का सिंचन होता है, वहीं सूर्य की रश्मियों की प्रचुर ऊर्जा से उस अमृत तत्व की शरीर में स्थिरता होती है इसीलिए कार्तिक मास में प्रात? पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु शालीग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इन दिनों ब्रजवासी जी कार्तिक माहात्म्य के माध्यम से श्रद्धालुओं को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में संयम एवं धर्म में चलने की प्रेरणा मिलती है। जीवन को उन्नत बनाने में संयम का बहुत महत्व है। संयमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं छोड़ता। शालिग्राम पूजन में पंचामृत का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा गाय का दूध, दही, घी व शहद और शक्कर से शालिग्राम भगवान का अभिषेक करना चाहिए। वस्तुतः इन पांचों का मंत्रोच्चारण के साथ मिल जाना ही पाँच प्रकार के अमृतों का मिलना है। इसमें तुलसीदल डाल देने के बाद यह चरणामृत बन जाता है जिसका प्रसाद में ग्रहण कर लेने पर सभी प्रकार की आधियाँ-व्याधियाँ अर्थात मानसिक रोग तथा शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। हमारी उपासना विधियाँ जहाँ मनुष्य को धार्मिक बनाती है वही शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ भी बनाती है।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

ज्वालामुखी बन सकती है मजदूर आंदोलन की चिंगारी

मनोज कुमार अग्रवाल

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नोएडा में कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये नई अंतरिम दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। नोएडा में 13 अप्रैल को हुए श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन के बाद आज पूरे दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट है।मजदूरों के गुस्से को देख कर सरकार आनफुट आ गयी है। केंद्र सरकार मामले की मानिटरिंग कर रही है वहीं यूपी हरियाणा राजस्थान की प्रदेश सरकारें अपने अपने स्तर पर मजदूरों के आंदोलन के शमन और मजदूरों को भड़काने वाले लोगों की पहचान करने में लगे हुए हैं। सरकार का मानना है कि यह समिति संवाद और आपसी सहमति के जरिए विवादों को सुलझाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और औद्योगिक माहौल स्थिर बना रहे।

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वेतन बढ़ोत्तरी समेत सामाजिक सुरक्षा के कई बिंदुओं को लेकर मजदूरों के आंदोलनों व उग्र प्रदर्शनों ने केंद्र तक को सतर्क कर दिया है। दरअसल, हरियाणा से शुरू हुई आग उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। हरियाणा से सटे राजस्थान के इक्के दुक्के स्थानों पर छिटपुट घटना होकर फिलहाल शांत है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एलपीजी गैस नहीं मिलने से मजदूरों की परेशानी बढ़ी हुई थी और उनका गुस्सा आंदोलन में तब्दील हो गया।

पता हो कि दिल्ली से सटे नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का गुस्सा अब एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में फैला हुआ एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. वेतन वृद्धि, महंगाई और श्रम सुविधाओं को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब कई जिलों में असर दिखा रहा है. नोएडा में चल रहे इस आंदोलन की शुरूआत 7 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर इलाके से हुई थी, जहां मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था.इसके बाद यह विरोध धीरे-धीरे नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंचा. अब इस आंदोलन का असर गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ तक में भी दिखाई दे रहा है. आज बड़ी संख्या में बुलंदशहर और गाजियाबाद में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम कर दिया. गाजियाबाद में स्थिति इतनी खराब हो गई कि नोएडा-गाजियाबाद बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

जान लीजिए नोएडा में यह आंदोलन 9 अप्रैल को फेस-टू थाना क्षेत्र में मौजूद होजरी कंपलेक्स से शुरू हुआ. जहां गारमेंट और होजरी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर फैक्ट्रियों के बाहर इकट्ठा हुए. वो वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. शुरूआत में यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था. मजदूरों ने नारेबाजी और बातचीत के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कीअप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक आंदोलन बिना किसी हिंसा के चलता रहा. हालांकि, मजदूरों का कहना था कि उनकी मांगों पर कंपनियों और प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके बीच असंतोष लगातार बढ़ता गया. मजदूरों के आंदोलन की स्थिति ने 12 अप्रैल को बड़ा मोड़ लिया. ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थर्ड इलाके में प्रदर्शन के दौरान मिंडा कंपनी के पास हालात अचानक बिगड़ गए. इस दौरान पुलिस कार्रवाई में गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें एक महिला मजदूर को गोली लग गई.यह घटना पूरे आंदोलन के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. जैसे ही गोलीकांड की खबर फैली, मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया और आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया.

अगले ही दिन 13 अप्रैल यानी सोमवार की सुबह नोएडा के फेस-2, सेक्टर-62 और एनएच-9 जैसे प्रमुख इलाकों में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए. इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी. डिवाइडर पर चढ़कर नारेबाजी की. कई जगह वाहनों को रोक दिया. इस दौरान हालात तेजी से बिगड़े और कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

नोएडा के फेस-2 इलाके में कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया. इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस और मजदूर आमने-सामने आ गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद किसी तरह हालात को काबू में लाया गया, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

इस आंदोलन का सीधा असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक ढांचे पर पड़ा. फेस-2 के होजरी कंपलेक्स में करीब 500 कंपनियां संचालित होती हैं. वहीं, इकोटेक थर्ड के औद्योगिक क्षेत्र में भी करीब 400 से अधिक फैक्ट्रियां और निजी कंपनियां हैं. इनमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं. दोनों प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ और कई कंपनियों को अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ा. यह आंदोलन किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि कई कंपनियों के मजदूरों का सामूहिक विरोध है. अब इसका असर पूरे एनसीआर में दिखने लगा है. गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे जिलों में भी मजदूर सक्रिय हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक होने की आशंका है.

मजदूरों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह करना, ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना, साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना, समय पर वेतन भुगतान, सैलरी स्लिप देना और बोनस को सीधे बैंक खाते में समय पर भेजना शामिल है. उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा वेतन से गुजारा संभव नहीं है.

आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम वेतन देश में सबसे अधिक है भाजपा के लिए परेशानी बढ़ेगी क्योंकि ये चारो राज्य भाजपा शासित हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर इन राज्यों की बैठकें कर स्थिति को संभालने की कोशिश होगी। उद्योगों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है और मजदूरों का ध्यान रखने की भी। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए लेकिन उद्योगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए।

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जिस तरह आग फैली है उसमें राजनीतिक मंशा देखी जा रही है क्योंकि अगले साल की शुरूआत में ही वहां चुनाव है। राजस्थान में भी न्यूनतम वेतन अपेक्षाकृत कम है लेकिन वहां भिवाड़ी के अलावा किसी स्थान पर कोई घटना नहीं हुई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है। गठित समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त को सौंपी गई है खास बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के पांच प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।सरकार की प्राथमिकता मजदूरों के असंतोष को दबाने कम करने और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए उकसाने मे नाकाम करने की है इसके लिए सरकार मजदूरों के हित मे हर कदम उठाने को तैयार है।

हाथियों की विरासतः जैव विविधता और पर्यावरण का अनमोल हिस्सा

सुनील कुमार महला

पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान, विशालकाय और सामाजिक जीवों में से एक हाथी को 'पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर' कहा जाता है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और इनके घटते अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को 'हाथी बचाओ दिवस' मनाया जाता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हाथी अनेक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार (विशेषकर हाथीदांत के लिए), वनों की कटाई, प्राकृतिक आवास का विनाश, मानव-हाथी संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। हाथी जंगलों, घासभूमियों और जल स्रोतों के संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है।

पाठकों को जानकारी देता चलूं कि हाथी पारिस्थितिकी तंत्र(इको-सिस्टम) को कई तरीकों से समृद्ध करते हैं।मसलन, वे फलों और पौधों को खाकर लंबी दूरी तय करते हैं और अपने मल(लीद) के माध्यम से बीजों का प्रसार करते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है और वनों का विस्तार बना रहता है। घने जंगलों में चलते समय वे टहनियाँ और झाड़ियाँ तोड़ते हैं, जिससे वन का घनत्व कम होता है और सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचता है, जिससे छोटे पौधों और घास को बढ़ने का अवसर मिलता है और जैव विविधता बनी रहती है। सूखे के समय हाथी अपनी सूंड और पैरों से जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिससे बने गड्ढे अन्य जानवरों के लिए भी जल स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा हाथियों के चलने से प्राकृतिक मार्ग (कॉरिडोर) बनते हैं, जो अन्य जीवों की आवाजाही को सरल बनाते हैं। उनका मल मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान कर उसे उर्वर बनाता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर हाथियों से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत में हाथियों की उपस्थिति मुख्य रूप से कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट (2017) के अनुसार भारत में लगभग 29,000-30,000 जंगली हाथियों का अनुमान था, जबकि 2025 की नवीनतम डीएनए आधारित गणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 22,446 आंकी गई है। डीएनए आधारित गणना का अर्थ है जानवरों की संख्या का अनुमान उनके आनुवंशिक पदार्थ (जेनेटिक मैटेरियल) के आधार पर लगाना, न कि केवल प्रत्यक्ष रूप से देखकर गिनना। विश्व में हाथियों की दो प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं-अफ्रीकी हाथी जिनकी संख्या लगभग 4-5 लाख है तथा एशियाई हाथी जिनकी संख्या लगभग 50,000-60,000 के बीच है। भारत विश्व के कुल एशियाई हाथियों का 60% से अधिक हिस्सा रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में मानव-हाथी संघर्ष वर्तमान समय की एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या बन चुका है। इसका मुख्य कारण वनों का सिकुड़ना, कृषि विस्तार, मानव बस्तियों का बढ़ना और हाथियों के प्राकृतिक मार्गों (कॉरिडोर) का टूटना है। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष औसतन 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हाथियों के हमलों में होती है। वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 628 तक पहुँच गई, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले पाँच वर्षों में 2,800 से अधिक मानव मौतें दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2009-2024 के बीच लगभग 8,000 मानव मौतें हुई हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ हैं।

दूसरी ओर, हाथियों की मृत्यु भी मानव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में हो रही है। पिछले 16 वर्षों में 1,653 हाथियों की मौत मानवजनित कारणों से हुई है, जिनमें लगभग 69% मौतें बिजली के करंट से और लगभग 16% रेल दुर्घटनाओं से हुई हैं। पिछले पाँच वर्षों में 528 हाथियों की मौत दर्ज की गई है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन 100 से अधिक हाथी मानव-हाथी संघर्ष में मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार, जहर देकर मारना तथा पटाखों या जहर मिले फलों से भी हाथियों की मृत्यु के मामले सामने आते रहे हैं। हाल ही में केरल में पटाखों से भरे फल खाने से हाथी की मृत्यु हुई तथा कर्नाटक में किसान की हाथी हमले में मृत्यु की घटना भी दर्ज की गई।

एक गंभीर घटना 20 दिसंबर 2025 को असम के होजाई जिले में हुई, जहाँ सैरंग-नई दिल्ली एक्सप्रेस

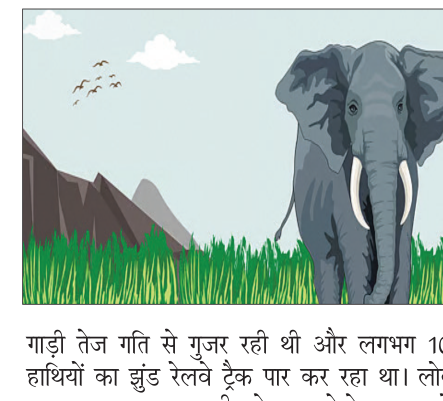

गाड़ी तेज गति से गुजर रही थी और लगभग 100 हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। लोको पायलट द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुक सकी और टक्कर हो गई, जिसमें 7 हाथियों की मौके पर तथा एक घायल हाथी की बाद में मृत्यु हो गई, इस प्रकार कुल 8 हाथियों की जान गई। यह घटना उस क्षेत्र में हुई जहाँ हाथियों का प्राकृतिक आवागमन रेलवे ट्रैक के पास से होता है, लेकिन सुरक्षा उपायों और चेतावनी प्रणालियों की कमी के चलते यह हुआ। इस प्रकार भारत में जहाँ एक ओर मानव जीवन हाथियों के कारण प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हाथी भी मानव गतिविधियों से गंभीर खतरे में हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दशार्ती है कि जंगलों का संरक्षण, हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा, सुरक्षित रेलवे और बिजली व्यवस्था, तकनीकी निगरानी (जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम) तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, ताकि मानव और वन्यजीव दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण सुरक्षित रह सके।

स्मार्ट मीटर के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन कर की रोड जाम

हसनपुर/अमरोहा (सब का सपना):- बुधवार को मोहल्ला हिरन वाला की दर्जनों महिलाओं ने स्मार्ट मीटर के भारी-भरकम बिलों और कथित मनमानी रीडिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हसनपुर-गजरौला मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कोतवाल राजेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित कुमार, कस्बा इंचार्ज अंकित मलिक और महिला उप निरीक्षक नेहा नेहरा ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को शांत कराया और उनकी मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हुआ। विद्युत उपखंड अधिकारी ने बताया कि महिलाओं ने स्मार्ट मीटर की रीडिंग और भारी बिलों की शिकायत की है। जिसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं महिलाएं जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रही थी।

इस दौरान प्रदर्शन में मुख्य रूप से कलुआ प्रजापति, आसमा, प्रीति देवी, मूर्ति देवी, गेंदा देवी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं।

सशक्त नारी, सशक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक भव्य रैली का आयोजन

अमरोहा (सब का सपना):- शहर में ह्यसशक्त नारी, सशक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा कार्यकताओं और स्थानीय महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली की शुरूआत शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति से हुई, जहां सभी प्रतिभागियों ने एकत्र होकर नारी सशक्तिकरण का संकल्प लिया। रैली में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए नारे लगाए। नारे जैसे सशक्त नारी, सशक्त भारत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत गूंजते रहे। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकताओं ने रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। रैली गांधी मूर्ति से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों और प्रमुख सड़कों से गुजरी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रतिभागियों ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकारों पर जागरूकता फैलाई। नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई मिली है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। रैली का उद्देश्य समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करना और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। यह रैली सशक्त नारी, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करती है। भाजपा कार्यकर्ता भविष्य में भी ऐसी गतिविधियां जारी रखने का संकल्प लेते हैं, ताकि हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त बन सके।

गांव सलेमपुर गोसाई में धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती, सेवादारों ने समर्थकों को कराया जलपान

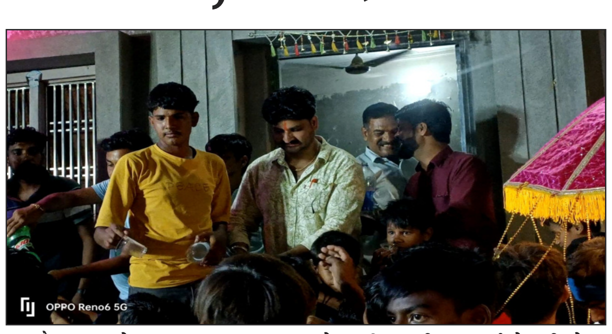

गजरौला/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के गजरौला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सलेमपुर गोसाई में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बड़े ही धूम-धाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ।इस दौरान गांव में शोभायात्रा का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया ।शोभायात्रा में शामिल भीम समर्थकों की सेवा हेतु गांव निवासी लोगों द्वारा जलपान की व्यवस्था भी कराई गई।

बता दें कि मंगलवार की देर शाम 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में एक शोभा यात्रा का आयोजन कराया गया। जिसमें भीम समर्थकों ने शोभायात्रा में शामिल डीजे की धुन पर जमकर डांस किया साथ ही 'भीमराव अंबेडकर अमर रहे' के नारे भी लगाए। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलग दिखाई दिया। वही गांव निवासी लोगों सोमपाल सिंह नागर, सौरभ नागर आदित्य नागर एवं कृष्ण नगर के परिवार वालों ने यात्रा में शामिल समर्थकों के लिए जलपान की व्यवस्था कराई जिसमें उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों को फल आहार, कोल्डड्रिंक , रुआबजा आदि वितरित कर आपसी भाईचारे की मिशाल कायम की। इस बारे में सोमपाल सिंह नागर एवं कृष्ण नागर ने बताया कि हमारे परिवार द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब की जयंती निकलती है तो हम इसी प्रकार लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

यातायात पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया चैकिंग अभियान

अमरोहा (सब का सपना):- पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में कुशल निर्देशन में बुधवार को यातायात पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर चैकिंग की गयी ।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ा प्रहार करते हुए यातायात पुलिस द्वारा पटाखों जैसी तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले मोडिफाइड साइलेंसर,मानक के विरुद्ध नंबर प्लेट (दोषपूर्ण/फॉल्टी नंबर प्लेट), तीन सवारी , बिना हेल्मेट तथा वाहनों पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई।

आयोजित अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 342 चालान किए गए । एवं शहर के चौराहो तथा तिराहो से अतिक्रमण हटवाया गया ।

जिलाधिकारी जनपद अमरोहा के आदेश के अनुपालन में 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाये गए विशेष अभियान के अन्तर्गत बिना फिटनेस, बिना परिमिट स्कूली वाहनो को चैक किया गया। जोया चौराहे पर सडक के किनारे नो-पार्किंग में खडे वाहनो के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गयी । मोडिफाइ साइलेन्सर, हूटर से सम्बन्धित अभियान के अन्तर्गत उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गयी । यातायात पुलिस द्वारा स्पीड लेजर गन से ओवर स्पीड मे चलते 75 वाहनो के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की गयी ।

श्री राम किसान किसान इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

नौगावा सादात/अमरोहा (सब का सपना):- श्री राम किसान किसान इंटर कॉलेज, बादशाहपुर, नौगावा सादात (अमरोहा) में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा के तत्वाधान में सचिव/न्यायाधीश अभिषेक कुमार व्यास के निर्देशन में एक विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं स्थानीय प्रतिभागियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में महेश सिंह ने किशोर एवं किशोरियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का स्पष्ट विजन निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बाल तस्करी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जब किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध या धोखे से ले जाकर उससे काम करवाया जाए या किसी गलत गतिविधि में धकेला जाए, तो उसे बाल तस्करी कहा जाता है। उन्होंने आगे बाल तस्करी के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें बाल मजदूरी, यौन शोषण, भीख मंगवाना, घरेलू काम या बंधुआ मजदूरी तथा अवैध गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना शामिल है। उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर सामाजिक अपराध है जिसे रोकने के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बाल तस्करी के तरीकों जैसे गरीब परिवारों को नौकरी का झांसा देना, बच्चों का अपहरण, परिचितों द्वारा धोखा तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाने जैसी घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतर जोखिम गरीब, अनाथ, स्कूल से वंचित तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को होता है। भारत में बाल तस्करी एक गंभीर अपराध है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC), पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) तथा किशोर न्याय अधिनियम ((Juvenile Justice Act) के अंतर्गत कड़ी सजा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। पीएलवी कुलदीप कुमार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं पीएलवी जयदेव सिंह ने पुलिस प्रक्रिया एवं एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आनंद कुमार एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में पीएलवी महेश सिंह, कुलदीप कुमार, जयदेव सिंह एवं शोभित कुमार की सक्रिय सहभागिता रही।

सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न

अमरोहा (सब का सपना):- सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहुत की गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव एवं मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र ने सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियो को बुके देकर स्वागत किया। कंवर सिंह तंवर ने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत से करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाएं और प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें। कहा कि उसी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं और योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास एवं निर्माण कार्यों में लगाए गए शिलापट्ट पर शासनादेशानुसार जनप्रतिनिधियों का नाम अवश्य अंकित किया जाए।

सांसद ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाइवे किनारे कई स्थानों पर अवैध कट बना लिए गए हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं बंद कराने के निर्देश दिए। इसके साथ हाइवे किनारे बने नालों में जलभराव की समस्या के निस्तारण के लिए सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को नियमानुसार राशन वितरण कराने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर की समस्या नहीं होनी चाहिए। जनपद में पर्याप्त मात्रा में सिलेण्डी की मात्रा रहे ताकि किसी को काई समस्या न हो। इसके लिए लगातार निगरानी हो और पूर्व प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एआरटीओ को निर्देशित किया कि विशेष प्रवर्तन कार्रवाई कर जनपद में बिना परमिट और अवैध रूप से चलने वाहनों को बंद कराया जाए। उन्होंने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि तोड़ी गई सड़कों को गुणवत्तापरक तरीके से ठीक कराया जाए और शेष बाकी कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। पूर्ण सहित चल रही योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि कि किसानों को मकाने बनाने के मिट्टी लाते हुए अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी को इस हेतु निर्देश जारी किये जाये जिससे कि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ बार बार अवैध खनन करने वालों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुये कहा कि कि यह योजना प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना है, इसलिए स्वच्छता को कार्यों में कोई लापरवाही न हो। सफाईकर्मियों की जिस ग्राम में तैनाती है उसमें वह अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करते हुए सफाई कार्य करे। जिन ग्रामों में सफाई न करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हो रही हैं, उसका समाधान किया जाए।

सांसद ने ग्रामों में कैम्प लगाकर शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या के निजात के लिए ई-रिक्शा के लिए सिस्टेमेटिक वे बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।

विधान परिषद सदस्य डॉ0 जयपाल सिंह व्यस्त ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता की समस्या के सम्बन्ध में अपनी बात रखी। जिस पर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से उच्च स्तर पर बात कर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त करने की बात कही। सदस्य विधान परिषद सत्यपाल सिंह सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों की उपयोगिता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ उन्होंने अवैध खनन पर कार्रवाइ करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में अपनी बात रखी। विधायक नौगांवा सादात समरपाल सिंह ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 49 ग्रामों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही। इसके साथ उन्होंने नौगांवा सादात से जोया के लिए चलने वाली इलेक्ट्रिक बस के बारे में जानकारी प्राप्त की।

अध्यक्षा न0पा0प0 अमरोहा शशि जैन ने निजी विद्यालयों में स्कूल ड्रेस, कोर्स और फीस सम्बन्धी एवं आर0टी0ई0 पोर्टल समस्याओं को रखा, जिस पर सांसद ने जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सांसद को आश्वस्त करते हुए कहा कहा कि जो भी निर्देश दिये गये हैं उन पर गम्भीरता के साथ शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा उदयगिरि गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, डीएफओ ब्लॉक प्रमुख हसनपुर ममता गुर्जर, अध्यक्ष नगर पंचायत पालिका हसनपुर राजपाल सैनी, हिमांशु त्यागी, परियोजना निदेशक डीआरडीए अम्बरीष कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी और जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अंबेडकर जयंती पखवाड़े में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का लिया संकल्प

चंदौसी/संभल(सब का सपना):- डॉ. भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव पखवाड़े के अंतर्गत बुधवार को चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर चितौरी स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बाबा साहब के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाई गई कि वे बाबा साहब के बताए मार्ग– शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो –पर चलते हुए अन्याय, भेदभाव और शोषण के खिलाफ निरंतर संघर्ष करेंगे। साथ ही समाज को सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं और एक समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर विनीत कुमार, मनीष कुमार, वीरपाल सिंह, अजय कश्यप सहित सैकड़ों आंबेडकरवादी मौजूद रहे।

इसके बाद चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के गांव मौलागढ़ मोजमपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। यहां आयोजित जनसभा में ढऊअ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकजुटता और मजबूती पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने और विजय प्राप्त करने का आह्वान किया।

संदिग्ध हालत में मिला ग्रामीण का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

धनारी/संभल(सब का सपना):- जनपद के धनारी थाना क्षेत्र के भिरावटी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब ट्यूबवेल पर सो रहे एक ग्रामीण का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह परिजनों ने जब ग्रामीण को ट्यूबवेल पर मृत अवस्था में देखा तो घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

परिवार परामर्श केंद्र की बैठक 13 मामलों की सुनवाई, दो में हुआ आपसी समझौता

चंदौसी/सम्भल(सब का सपना):- जनपद में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा संचालित परिवार परामर्श सुलह-समझौता केंद्र की बैठक बुधवार को चंदौसी स्थित गौशाला रोड पिंक चौकी में आयोजित की गई। यह बैठक पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) कुलदीप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में केंद्र प्रभारी डॉ. रुकम पाल सिंह की देखरेख में संपन्न हुई।

बैठक में पति-पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवादों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों की सुनवाई की गई। परामर्श केंद्र में मौजूद काउंसलरों द्वारा दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए आपसी संवाद स्थापित कराया गया और विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया गया। इस दौरान दो परिवारों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराने में सफलता प्राप्त हुई, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं।

अन्य मामलों में विस्तृत चर्चा के बाद अगली तिथि निर्धारित की गई, ताकि दोनों पक्षों को और बेहतर तरीके से समझाकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि परिवार परामर्श केंद्र का मुख्य उद्देश्य टूटते हुए परिवारों को बचाना और आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराना है।

बैठक के दौरान काउंसलर श्वेता गुप्ता, उपनिरीक्षक महेश गंगवार, रुचि, होमगार्ड करुणा सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने मिलकर मामलों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत स्कूटी रैली का आयोजन

सैकड़ों महिलाओं की भागीदारी, नारी सशक्तिकरण का दिया सशक्त संदेश

सम्भल(सब का सपना):- जनपद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उपलक्ष्य में बुधवार को एक विशाल एवं ऐतिहासिक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ हयातनगर मंडल के पक्का बाग सरायतरीन से हुआ, जो सम्भल शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भाजपा कार्यालय पर जाकर सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सम्भल के नामित सभासद सैय्यद शान अली के साथ सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक रहा।

रैली के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह, आत्मविश्वास और जोश देखने को मिला। यह आयोजन केवल एक रैली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नारी सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की मजबूत अभिव्यक्ति बनकर सामने आया। हर बहन-बेटी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई दी, जो यह संदेश दे रही थी कि आज की नारी समाज और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने सभी से आह्वान किया कि नारी सम्मान और सशक्तिकरण के इस अभियान को और मजबूती प्रदान करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा।

इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता, जिला महामंत्री शिल्पी गुप्ता, जिला मंत्री सोनू चहल, गणेश शर्मा, सुरेश अटल, सैय्यद शान अली, पारुल शर्मा, कशिश कौशल, मनोज राणा, जितेन्द्र सैनी, निशि, निशा, श्रवण कुमार, बंटी सागर, खुशीर्दा, रूबी बेगम, सूफिया बेगम, इलमा परवीन, नसरीन, फातमा बानो, खानम, हिना परवीन, शहीना परवीन, नजरिन बानो, रेशमा परवीन, सकीना परवीन, सिमरन फातमा, रानी परवीन, अजीज फातमा, सितारा बेगम, रुकसाना परवीन, शहनाज फातमा, सतीश, प्रमोद सैनी, अब्दुल हकीम, शकील अंसारी, परवीन, अमलेश, प्रियंका सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही।

वाहन लूट के लिए पिता-पुत्र की हत्या करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

धनारी/संभल(सब का सपना):- जनपद के थाना धनारी क्षेत्र से लापता हुए पिता-पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वाहन लूटने की योजना बनाकर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शवों को शामली के खेतों में छिपा दिया था।

मामले की शुरूआत 4 अप्रैल को हुई, जब ग्राम मलुआ के घेर, भिरावटी निवासी रामसरन पुत्र विशम्बर ने सूचना दी कि उसका भाई नरेश (41) और भतीजा भीमसैन (19) 2 अप्रैल की शाम अपनी भाड़े की बोलेरो गाड़ी से मेरठ लेबर लाने के लिए गए थे। उसी रात आखिरी बार दोनों से बातचीत हुई, जिसके बाद उनके मोबाइल फोन बंद हो गए। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला।

इस सूचना पर थाना धनारी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और 6 अप्रैल को मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर्विलांस व जांच के दौरान 7 अप्रैल को जनपद शामली के कोतवाली क्षेत्र के काबड़ौत गांव के खेतों में दो अज्ञात शव मिले, जिनकी शिनाख्त परिजनों ने नरेश और भीमसैन के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं।

जांच के दौरान घटना में शामिल अभियुक्त मनोज पुत्र महावीर का नाम सामने आया, जिसे 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। मनोज से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अरविंद पुत्र जोगेंद्र और संतोष पुत्र जोगेंद्र के नाम भी प्रकाश में आए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और उन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

मंगलवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने अरविंद को आर्थल चौराहा से टिकटा रोड स्थित गौरीपुर तिराहा खरंजा मार्ग, थाना धनारी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने भाई संतोष और साथी मनोज के साथ मिलकर 2-3 अप्रैल की रात वाहन लूटने की योजना बनाई थी।

उन्होंने नरेश और भीमसैन की गाड़ी बुक कराई और मौका पाकर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शवों को शामली क्षेत्र के खेतों में छिपा दिया और बोलेरो पिकअप लेकर फरार हो गए।

अरविंद की निशानदेही पर उसके घर से मृतकों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब फरार आरोपी संतोष की गिरफ्तारी और लूटे गए वाहन की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का पूर्ण खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष

गलती का एहसास होने पर मांगी माफी, पत्रकारों से मामला न उछालने की अपील

संभल(सब का सपना):- जनपद के हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित सरायतरीन मोहल्ला कोटला में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अब्दुल हकीम द्वारा फेसबुक पर की गई एक पोस्ट के बाद मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

बताया जा रहा है कि अब्दुल हकीम ने बीती रात अपने फेसबुक अकाउंट पर एक रुपए के नोट पर अपनी

फोटो लगाकर पोस्ट साझा कर दी थी। पोस्ट में लिखा गया था कि जिसे 1 रुपए की कीमत पता हो, वह कभी करोड़ों मिलने पर घमंड नहीं करता। इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट कुछ लोगों द्वारा लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दी गई।

मामला बढ़ता देख अब्दुल हकीम बैकफुट पर आ गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित हयातनगर थानाध्यक्ष से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह पोस्ट उनसे गलती से हो गई और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।

साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भावुक अपील करते हुए कहा कि इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए और उन्हें बेवजह बदनाम न किया जाए। उन्होंने कहा, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।

किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, समाधान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

चंदौसी/संभल(सब का सपना):- तहसील परिसर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष (अराजनैतिक) के उपाध्यक्ष रजत सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसडीएम चंदौसी को सौंपा गया। ज्ञापन में नगर पालिका परिषद चंदौसी पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और आमजन को परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए गए।

यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि घर-घर जल योजना के तहत कराए जा रहे कार्य मानकों के विपरीत हो रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा मनमानी करते हुए दो दिन में पूरा होने वाला काम एक महीने बाद भी अधूरा पड़ा है। आवास विकास मुख्य मार्ग को एक माह पहले खोद दिया गया, लेकिन

अभी तक कार्य पूरा नहीं होने से स्कूली बच्चों, मरीजों, कर्मचारियों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा सीकरी गेट पुलिस चौकी मार्ग पर कराए गए सड़क निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए गए। यूनियन का आरोप है कि सड़क बनने के कुछ ही घंटों में उखड़ गई, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका अधिकारी अपने निजी ठेकेदारों से काम कराकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में नगर में लगाए जा रहे स्ट्रीट लाइट कार्य में भी भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। यूनियन का कहना है कि एक-एक लाइट का भुगतान कई गुना अधिक किया जा रहा है, जिससे कमीशनखोरी का संदेह है। साथ ही अवैध खनन और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायत भी की गई है। यूनियन ने मांग की है कि संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, सीकरी गेट के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाए।

अंत में यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सम्भल गेट पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका और प्रशासन की होगी।

शाहजहां कालीन कारवां सराय प्रवेश द्वार का हुआ भव्य जीर्णोद्धार

संभल में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, डीएम और एएसआई की संयुक्त पहल सफल

संभल(सब का सपना):- जनपद के सोंधन मुहम्मदपुर स्थित ऐतिहासिक कारवां सराय का प्रवेश द्वार एक बार फिर अपने पुराने गौरव के साथ खड़ा नजर आ रहा है। शाहजहां काल का यह महत्वपूर्ण स्मारक करीब नौ महीने तक चले जीर्णोद्धार कार्य के बाद पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मेरठ मंडल द्वारा संरक्षित इस धरोहर के संरक्षण कार्य में जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया की अहम भूमिका रही।

एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् विनोद सिंह रावत के निर्देशन में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस ऐतिहासिक प्रवेश द्वार को नए स्वरूप में संवारा गया। मुगलकालीन वास्तुकला का यह उत्कृष्ट नमूना लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, लेकिन अब इसके मेहराब, दीवारें और दो मंजिला संरचना फिर से अपनी भव्यता बयां कर रही हैं। प्रवेश द्वार में केंद्रीय मार्ग के साथ दोनों ओर पहरेदारों के कमरे और उन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों व मेहराबदार संरचना को भी पुनर्स्थापित किया गया है।

इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया का विशेष योगदान रहा। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए स्मारक के आसपास के अवैध और अव्यवस्थित निर्माणों को हटवाया, जिससे एएसआई को बिना किसी बाधा के कार्य पूरा करने में मदद मिली। उनके कुशल नेतृत्व के चलते यह जटिल कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सका।

कारवां सराय के इस कायाकल्प से अब संभल में पर्यटन को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोगों को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। स्मारक की देखभाल के लिए विभाग द्वारा भविष्य में कर्मचारी नियुक्त करने की भी योजना बनाई गई है। इसके साथ ही एएसआई ने जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की भी तैयारी शुरू कर दी है। आगामी योजनाओं में सोंधन मुहम्मदपुर स्थित कारवां सराय की मस्जिद, फिरोजपुर का प्राचीन किला, चंदायन के चंद्रेश्वर खेड़ा और गुमथल खेड़ा के प्राचीन स्थलों का संरक्षण शामिल है। प्रशासन और एएसआई का यह संयुक्त प्रयास संभल को एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एंबुलेंस स्टाफ की तत्परता से बची जच्चा-बच्चा की जान,परिवार में खुशी का माहौल

रजपुरा/संभल(सब का सपना):- जनपद के रजपुरा ब्लॉक के लहरारत्तू गांव में 102 एंबुलेंस स्टाफ की तत्परता से एक महिला का सुरक्षित प्रसव एंबुलेंस में ही कराया गया। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी राजू की पत्नी गीता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस पर राजू ने तत्काल 102 एंबुलेंस सेवा पर सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस के ईएमटी मोहित कुमार और पायलट

प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और प्रसूता को एंबुलेंस में लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए।

रास्ते में गीता की प्रसव पीड़ा अधिक बढ़ गई, जिस पर ईएमटी मोहित कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए एंबुलेंस को रास्ते में रुकवाया और सुरक्षित तरीके से प्रसव कराया। महिला ने एंबुलेंस में ही एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।

प्रसव के बाद एंबुलेंस स्टाफ ने जच्चा-बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गवां में भर्ती कराया, जहां अस्पताल स्टाफ ने दोनों को स्वस्थ बताया।

प्रोग्राम मैनेजर अनिल कुशवाहा और जिला प्रभारी दया शंकर ने बताया कि एंबुलेंस स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में बेहतर सेवाएं देने में सक्षम हैं। परिजनों ने एंबुलेंस स्टाफ और EMRI GHS संस्था का आभार जताते हुए उनकी सराहना की है।

नोट पर फोटो लगाकर पोस्ट वायरल, पुलिस जांच में जुटी, युवक ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

संभल(सब का सपना):- जनपद के हयातनगर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा नोट पर अपनी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करना चर्चा का विषय बन गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं युवक का माफी मांगते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायतरीन के कोटला निवासी अब्दुल हकीम ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक नोट की तस्वीर साझा की थी, जिसमें उसकी खुद की फोटो लगी हुई थी। साथ ही उसने लिखा था– जिसे ₹1 की कीमत का पता हो वह कभी करोड़ मिलने पर घमंड नहीं करता। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कुछ लोगों ने इसे हाल ही में हुए नकली नोटों के मामले से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही इसी क्षेत्र में एटीएस द्वारा नकली नोटों के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।

सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और थाना पुलिस को जांच के निर्देश दिए। पुलिस की सक्रियता की जानकारी मिलने पर अब्दुल हकीम ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसका उद्देश्य किसी भी तरह की गलत गतिविधि करना नहीं था। उसने मुख्यमंत्री व प्रशासन से माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि यह केवल सोशल मीडिया स्टंट था या इसके पीछे कोई अन्य पहलू भी जुड़ा हुआ है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि संबंधित नोट असली था या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई थी।

हयातनगर थाना प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण उनसे बात नहीं हो सकी। अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं। यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया के दुरुपयोग और वायरल होने की होड़ पर सवाल खड़े करती है।

सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला, न्याय दिलाने का भरोसा

बिजनौर (सब का सपना):- समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चांदपुर क्षेत्र के ग्राम हैजरपुर पहुंचा, जहां प्रशांत सैनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा दिलाया कि पार्टी इस मामले में परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचा था। इस दौरान एटा से सांसद देवेश शाक्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम जनता में भय का माहौल है। पीड़ित परिवार ने प्रतिनिधिमंडल के सामने अपनी मांगें रखते हुए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी आवास और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। साथ ही मुख्य आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई।

निवर्तमान जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने आश्वासन दिया कि पार्टी इस प्रकरण की लगातार निगरानी करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। गौरतलब है कि ग्राम हैजरपुर निवासी 23 वर्षीय प्रशांत सैनी की दबंगों द्वारा कथित रूप से पिटाई किए जाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल में सांसद देवेश शाक्य, विधायक स्वामी ओमवेश, मनोज कुमार पारस, राम अवतार सिंह सैनी, तसलीम अहमद, जयपाल सिंह सैनी, डॉ. लाखन सिंह पाल, श्याम लाल बच्ची सैनी, डॉ. कुन्तेश सैनी और चौधरी संसार सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे।

किसान दिवस में गूंजी किसानों की आवाज

3 दिन में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी

बुलन्दशहर (सब का सपना):- राजकीय कृषि विद्यालय में मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, विद्युत विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला संरक्षक चौधरी कुलदीप गुड्डू (भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक) ने बताया कि किसानों ने विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। मुख्य विकास अधिकारी ने कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया तथा शेष के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

किसानों की प्रमुख मांगों में गंगा एक्सप्रेसवे पर लिंक रोड व सर्विस रोड निर्माण, स्मार्ट मीटर हटाने, आंगनवाड़ी व मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने, गेहूं खरीद में तेजी, एनसीईआरटी पुस्तकों का पालन, राहवीर योजना का लाभ, दूषित पानी की जांच व प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, फसल नुकसान का मुआवजा और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक शामिल रहीं।

किसानों ने चेतावनी दी कि जिला स्तर की समस्याओं का तीन दिन में समाधान नहीं होने पर बुलंदशहर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।

सरकारी भूमि से बिना नीलामी के काट ली गेहूं की फसल एसडीएम से की शिकायत

बेखौफ लोगों ने सरकारी भूमि चिन्हित होने के बाबजूद भी गेहूं की फसल काटी

शिकारपुर/बुलंदशहर (सब का सपना):- जनपद के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डोमला हसनगढ़ में सरकारी हड़वार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का शिकायत कताओं ने लगाया आरोप। बुधवार को महेंद्र पाल सिंह राजेश देवी मुकेश कुमार शिकारपुर तहसील पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है साथ ही शिकायतकताओं ने बताया है कि गांव के ही दो लोगों ने हड़वार की भूमि पर गेहूं की फसल बो कर बिना तहसील की इजाजत के काट ली है जबकि इस जमीन को राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार का सूचना का खेत में बोर्ड लगाकर चिन्हित किया गया था कि यह भूमि हड़वार है लेकिन गांव के ही लोगों ने उस पर गेहूं की फसल बो डाली और उस फसल को काट लिया गया जबकि नियमानुसार गेहूं की फसल की नीलामी होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया शिकायतकताओं ने एसडीएम से कहा है कि जांच कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जब इस संबंध में एसडीएम अरुण कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि शिकायतकताओं का इस मामले में एक शिकायती प्रार्थना पत्र मिला है जिसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा कराई जा रही है जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नमाज पढ़कर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला

गुलावठी/बुलंदशहर (सब का सपना):- नमाज पढ़ कर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे युवक घायल हो गया। युवक के पिता ने तीन लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में मोहल्ला पीर खाँ निवासी अकबर पुत्र समसुद्दीन ने बताया कि उसका पुत्र आयान मस्जिद से नमाज पढकर आ रहा था। तभी जन्नत मस्जिद के निकट मोहल्ले के ही रहने वाले अफनान पुत्र सफीमद्दीन उर्फ मन्यु, शमद पुत्र दिलशाद व वसीम पुत्र रफीक ने उसके पुत्र पर धारधार हथियार छुरी से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग उसके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। मोहल्ले के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

माता के भजनों पर झूमे श्रद्धालु, सुंदर-सुंदर झांकियां ने मोहा मन

गुलावठी/बुलंदशहर (सब का सपना):- नगर के मोहल्ला रामनगर में 18 वॉ मां भगवती का विशाल जागरण का आयोजन हुआ। जिसमें माता ब्रजेश्वरी जागरण मंडल के तत्वावधान में भव्य भव्य झांकियां निकाली गई। वही माता ब्रजेश्वरी जागरण मंडल के भजन गायक पंडित रामनिवास शर्मा के भजनों पर भक्त झूमते नजर आए। जागरण में राधा कृष्ण,भोला पार्वती, मां काली एवं मां शेरावाली की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।

पूरी रात्रि चले जागरण के बाद सुबह 4:00 महा आरती हुई।

आरती के बाद प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति के लोग बबलू शर्मा, राजीव प्रजापति, मोनू चौधरी, विशाल चौहान शाहिद समिति के अन्य पदाधिकारी और भगत मौजूद रहे।

नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, 150 मरीजों की जांच

गुलावठी/बुलंदशहर (सब का सपना):- नगर के धौलाना रोड स्थित सिटी क्लिनिक के तत्वाधान में इंडिया आई इंस्टीट्यूट के सहयोग द्वारा नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। जिसमें डॉ तन्नू राजपूत, डॉ अदिति चौधरी, डॉ प्रियंका गुप्ता ने शिविर में मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। जिसमें करीब 150 लोगों ने अपनी नेत्र जाँच कराई। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां दी गईं। सिटी क्लिनिक संचालक डॉ उवेश खान ने बताया कि आंख रोग, मोतियाबिंद,लेंस ऑपरेशन ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे। इसके अलावा पलक का रोग, पलक का उल्टा होना, पलक का बाहर मुड़ना, पलक की गांठ, तिरछापन, काला मोतिया की जांच शिविर में निशुल्क की गई है।

स्मार्ट मीटर के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, प्रीपेड व्यवस्था खत्म करने की मांग

बिजनौर (सब का सपना):- स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था के खिलाफ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। डी.के. फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के बैनर तले दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के नेशनल डिप्टी चीफ रिपोर्टिंग ऑफिसर मुस्तकीम अहमद ने किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर में लागू प्रीपेड प्रणाली आमजन, विशेषकर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गंभीर समस्या बन गई है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र का अधिकांश वर्ग दैनिक मजदूरी और छोटे व्यवसायों पर निर्भर है, ऐसे में बिजली के लिए अग्रिम भुगतान करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आरोप है कि मामूली बैलेंस समाप्त होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाती है, जिससे घरों में अंधेरा छा जाता है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखभाल पर भी पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रीपेड व्यवस्था को जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल समाप्त कर पूर्व की पोस्टपेड प्रणाली बहाल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जंगली कुत्तों के हमले में हिरण की मौत, दूसरा घायल

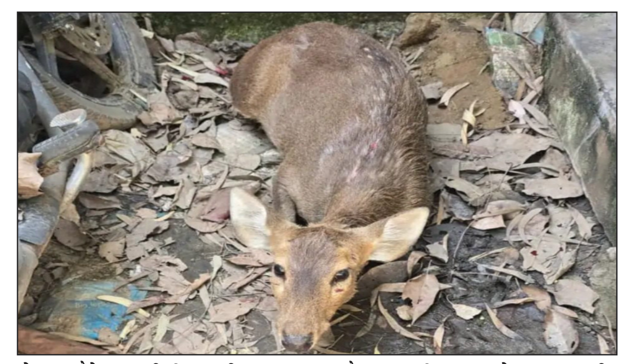

बिजनौर(सब का सपना):- जनपद के मंडावर थाना क्षेत्र में जंगली कुत्तों के हमले में दो मादा हिरण गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना ग्राम रावली मंडावर रोड के पास जंगल किनारे की है, जहां जंगली कुत्तों के झुंड ने दोनों हिरणों को घेरकर हमला कर दिया। हमले में कुत्तों ने हिरणों को बुरी तरह नोच डाला, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ीं।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों घायल हिरणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए भेजा। पशु चिकित्सकों की देखरेख में इलाज शुरू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण एक हिरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी हिरण की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में जंगली कुत्तों पर नियंत्रण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

सीएचसी स्योहारा का उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश

स्योहारा/बिजनौर (सब का सपना):- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. राहुल ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्योहारा का औचक निरीक्षण किया। दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचे डॉ. राहुल ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डॉ. बी.के. स्नेही ड्यूटी पर मौजूद मिले और मरीजों को देखते हुए पाए गए। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा इमरजेंसी, दवा स्टोर, कोल्ड चेन, ऑपरेशन थियेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया, जहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। डॉ. राहुल ने अधीक्षक को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और सभी कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन करें। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने जैसी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर उसका दैनिक विवरण जिला स्तर पर भेजने को कहा गया। उन्होंने निर्देशित किया कि ओपीडी में आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और आवश्यक जांचें अस्पताल में ही कराई जाएं। किसी भी मरीज को बाहर से दवा न लिखी जाए। इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए।

हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि सीएचसी में चार बेड आरक्षित किए गए हैं और आवश्यक दवाएं व उपकरण उपलब्ध हैं। साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और जागरूकता सामग्री के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।

उन्होंने गांव स्तर पर नियमित हेल्थ कैंप आयोजित करने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नियमित संचालित करने और टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों को परामर्श उपलब्ध कराने पर जोर दिया। आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

अधीक्षक डॉ. बी.के. स्नेही ने अस्पताल की रंगाई-पुताई, विद्युत वायरिंग और स्टाफ की कमी दूर करने की मांग रखी, जिस पर डॉ. राहुल ने विचार करने का आश्वासन दिया।

निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

भाजपा महिला मोर्चा ने विशाल महिला स्कूटी रैली का किया आयोजन

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जनपद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य और विशाल महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। रैली में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए उत्साह और जोश का परिचय दिया।

इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान और क्षेत्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सोम ने नारी सम्मान का अनूठा संदेश देते हुए मंच महिलाओं को समर्पित कर दिया और स्वयं नीचे खड़े रहकर व्यवस्थाओं का संचालन किया। यह पहल पूरे कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रही और उपस्थित जनसमूह ने इसकी सराहना की।

रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। रैली यमुना पुरम स्टेडियम से शुरू होकर नुमाइश फ्लाईओवर, काले आम चौराहा, मोती बाग, डिप्टी गंज, अंबर सिनेमा रोड और अंसारी रोड होते हुए राजे बाबू पार्क पर सम्पन्न हुई। रास्ते भर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल, महिला मोर्चा अध्यक्ष शशि शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाएं–शिक्षिकाएं, डॉक्टर, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता–उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं ने हाथों में साइन बोर्ड और नारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने सभी मातृशक्ति, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का सफल आयोजन के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह रैली समाज में महिला सम्मान और सशक्तिकरण का सशक्त संदेश देने में सफल रही है।

ग्राम आढा में स्कूल को मिली नई सौगात, विधायक ने किया लोकार्पण।

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जनपद के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आढा स्थित पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों और आधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण मुख्य अतिथि सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह द्वारा किया गया।

इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक व ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि नए कक्षों से पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और कंप्यूटर लैब से बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। विधायक ने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यालय स्टाफ भी उपस्थित रहे।

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर सो रहे तीर्थयात्रियों के 8 बैग चोरी, नकदी और सामान पर हाथ साफ

कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर पर स्नान के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों की बस से 10 बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। तीर्थ यात्री आधी रात को 1:00 बजे हरिद्वार से कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं के बैग में दवाइयां कपड़े और नकदी रखा था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर सो रहे तीर्थयात्रियों के 8 बैग चोरी, नकदी और सामान पर हाथ साफअज्ञात चोर बस के अंदर रखे सामान सहित बैग को लेकर फुर्र हो गए और यात्रियों को सुबह इसकी भनक लगी। पंजाब के पठानकोट से तीर्थ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वह दो दिन पहले हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए गए थे वहीं से मंगलवार की रात को 1:00 बजे कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पहुंचे थे।उन्होंने अपने बैग रात को बस में ही छोड़ दिए थे । जब सुबह यात्री उठकर स्नान के लिए ब्रह्मसरोवर पहुंचे तो बस से सामान गायब मिला। उन्होंने आस -पास इसके बारे में पता किया तो किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने इस बात पर कड़ा एतराज जताया की ब्रह्मसरोवर पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।उनके बैग में यात्रा के लिए जरूरी दवाइयां और नकदी भी रखी थीं। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वही यात्रा में पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने ब्रह्मसरोवर के आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

हरियाणा निकाय चुनाव में SC आरक्षण नोटिफिकेशन को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका, अधिसूचना रद करने की मांग

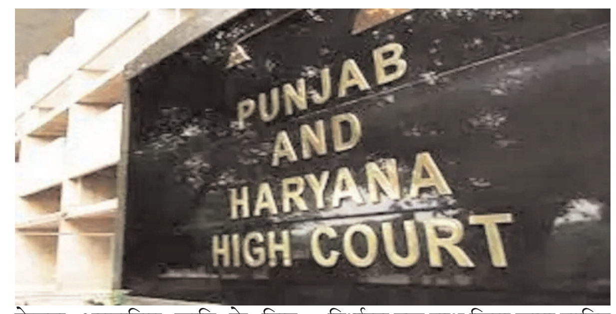

चंडीगढ़। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर जारी आरक्षण अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधी 10 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप सीमित रहता है। पंचकूला निवासी उषा रानी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका में अधिसूचना को असंवैधानिक और अधूरी बताते हुए रद करने की मांग की गई है। जस्टिस विकास बहल और जस्टिस रोहित कपूर की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की अधिसूचना जारी की, जबकि अन्य श्रेणियों सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का विवरण उसी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया।याचिका में यह भी तर्क रखा गया कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए सीटों का निर्धारण एक साथ किया जाना चाहिए था। अलग-अलग चरणों में आरक्षण तय करना चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधानिकता पर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की उस प्रक्रिया को भी चुनौती दी है, जिसमें जनगणना आंकड़ों की बजाय फैमिली इंफार्मेशन डेटा रिपाजिटरी (एफआईडीआर) के आधार पर सीटों का निर्धारण और आरक्षण किया गया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट संकेत दिया कि एक बार चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी हो जाने के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद सीमित रह जाती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि डिलिमिटेशन या आरक्षण से संबंधित आपत्तियां पूरी तरह से नहीं भी सुनी गई हों, तब भी यह स्वत याचिका का आधार नहीं बनता। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी मामलों में अदालतों का दखल स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इस परविधान के तहत न तो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) और न ही सीटों के आवंटन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और चुनाव से जुड़े विवाद केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाए जा सकते हैं। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो कोर्ट ने दोहराया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित हो जाता है। पीठ ने टिप्पणी की कि इस चरण पर याचिका पर सुनवाई करना व्यर्थ की कवायद साबित हो सकता है और याचिकाकर्ताओं को अपने सभी तर्क चुनाव याचिका के जरिए उठाने चाहिए। पीठ ने मामले की सुनवाई रोस्टर के अनुसार नियमित बेंच की सुनवाई के लिए गुरुवार तक स्थगित कर दी ।

पानीपत पुलिस पर गिरी गाज, जांच में लापरवाही पर एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश

पानीपत। थाना किला क्षेत्र में खेत में चचेरे भाइयों की ओर से मारपीट कर घायल करने के मामले में कार्रवाई न करना पुलिस को भारी पड़ गया। न्यायालय ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायालय के निर्देश के बाद थाना किला पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले के राजाखेड़ी निवासी राजेश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिविजन) की अदालत में याचिका दायर कर बताया कि अक्टूबर 2025 में वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके चचेरे भाइयों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका उपचार जिला नागरिक अस्पताल में कराया गया। इस मामले में पहले थाना किला में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी एसआई अनूप इस मामले में आरोपितों से दूर का रिश्ता होने के कारण मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष की शिकायत पर उल्टा उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया।राजेश ने न्यायालय में गवाह भी पेश किए, जिसके बाद अदालत ने मामले को गंभीर और संज्ञेय अपराध मानते हुए तत्कालीन एसएचओ नीरज, एसआई अनूप सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम : सशक्त भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम

चंडीगढ़ : भारत में महिलाओं की भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें बराबरी का स्थान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आया है। यह अधिनियम न केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी बनाता है, जहां महिलाओं की आवाज को समान महत्व मिलता है। इससे महिलाओं को नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह अधिनियम महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व नहीं देता, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि नारी शक्ति भारत की प्रगति का आधार है। उनका मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी देश तेजी से विकास करेगा। उनके नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को लाभार्थी से निमार्ता बनाने की दिशा में काम किया है। यानी महिलाएं अब केवल योजनाओं का लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि देश के विकास में सक्रिय भागीदार बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका जन्म दर में सुधार करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जन-धन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनीं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई, जिसमें उनकी शिक्षा और विवाह के लिए बचत की जाती है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ाया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिससे वे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिला नेताओं को नए अवसर मिलेंगे। नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होगा। मोदी सरकार का यह कदम भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। यह अधिनियम केवल राजनीतिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलेगी तथा लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यह महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अधिनियम के लागू होने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसे विषय अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का अनुभव पहले ही यह दर्शा चुका है कि महिला प्रतिनिधित्व से नीतियां अधिक जन-केंद्रित और प्रभावी बनती हैं। अब यही प्रभाव संसद और विधानसभाओं के स्तर पर दिखाई देगा, जिससे विकास की दिशा अधिक संतुलित और समावेशी होगी। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि पिछले एक दशक में तैयार की गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक व्यापक और जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण से देखा गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान ने सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाया है और लड़कियों की माध्यमिक स्तर की नामांकन दर 80.2 प्रतिशत तक पहुंची है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.6 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज की महिला केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।

अंगदान को लेकर बदली हरियाणा के लोगों की सोच, 7940 लोगों ने लिया संकल्प; जींद ने किया टॉप

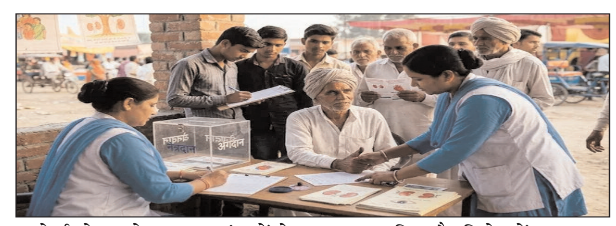

रोहतक। हरियाणा में अंगदान को लेकर लोगों की सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है। प्रदेश में कुल 7940 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। जबकि हमारे पड़ोसी पंजाब का आंकड़ा हमसे काफी अच्छा है। पंजाब में पंजीकरण 11274 तक पहुंच चुका है। अभी दोनों राज्यों के बीच में पंजीकरण का अंतर 3334 का है। इसलिए इस अभियान को तेजी से गति देने की जरूरत है। हालांकि जिलों के बीच आंकड़ों में बड़ा अंतर भी सामने आया है, जो जागरूकता के असमान स्तर को दशार्ता है। प्रदेश में जींद जिला 1076 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद गुरुग्राम के 973 पंजीकरण और फरीदाबाद के 791 पंजीकरण का नंबर आता है। सबसे निचले पायदान पर नूंह के 48, चरखी दादरी के 21 और पलवल के 21 पंजीकरण हैं, जहां जागरूकता अभियान की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निचले पायदान पर खड़े जिलों में जागरूकता बढ़ाई जाए तो हरियाणा इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। फिलहाल आंकड़े यह जरूर संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में अंगदान को लेकर डर से संकल्प की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे जनआंदोलन बनाने के लिए अभी और प्रयास जरूरी हैं।

नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में केवल 2 नए पंजीकरण हुए, जिनमें गुरुग्राम और अंबाला से एक-एक व्यक्ति शामिल है। यह संख्या बताती है कि शुरूआती उत्साह के बाद अब अभियान को और गति देने की जरूरत है। उम्र के आधार पर देखें तो युवा वर्ग इस अभियान में सबसे ज्यादा सक्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में जागरूकता और सोशल मीडिया की पहुंच इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। खासकर युवा वर्ग और पुलिस-सेना जैसे अनुशासित बलों के परिवार सबसे आगे आ रहे हैं। प्रदेश में सोटो के अनुसार ब्रेन डेड की स्थिति में व्यक्ति की वापसी संभव नहीं होती, ऐसे में अंगदान जीवनदान का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि अब पुलिस और सेना से जुड़े परिवारों के साथ-साथ युवा वर्ग भी बढ़-चढ़कर इस अभियान में भाग ले रहा है। राज्य में अंगदान के मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। वर्ष 2024 में जहां केवल 2 अंगदान हुए थे, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 4 से अधिक हो चुका है। साथ ही अब तक करीब 35 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। इस बदलाव के पीछे स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (सोटो) की अहम भूमिका रही है। सोटो ने पिछले दो वर्षों में गांव-गांव तक पहुंच बनाते हुए नुक्कड़ नाटक, स्कूल-कालेज सेमिनार और पंचायत बैठकों के जरिए लोगों को जागरूक किया है।डॉ. एचके अग्रवाल पीजीआइएमएस से मात्र 4 दिन के अंतराल में दो बार ग्रीन कोरिडोर बनाने और आपके समाचारों के सहयोग से लोगों में अंगदान की जागरुकता को लेकर डर कम हो रहा है।

पहले जहां लोग भ्रांतियों के कारण इससे दूर रहते थे, वहीं अब वे खुद सोटो कार्यालय में संपर्क कर प्रक्रिया की जानकारी ले रहे हैं। अंगदान एक ऐसा फैसला है, जिससे एक व्यक्ति 8 लोगों की जान बचा सकता है। मौत अटल है, लेकिन अंगदान के जरिए हम किसी के जीवन का आधार बन सकते हैं।

अब बदलेगा शहरी नक्शा : छोटे शहर बनेंगे विकास के नए पावरहाउस, नगर निकाय भी होंगे आत्मनिर्भर

चंडीगढ : देश के शहरी विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने शहरी चुनौती कोष (अर्बन चैलेंज फंड) और क्रेडिट रिपमेंट गारंटी सब-स्कीम (सीआ-रजीएसएस) को लांच किया। एक लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष के साथ चार लाख करोड़ निवेश का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें विशेष फोकस टियर-2 और टियर-3 शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने विधिवत रूप से अर्बन चैलेंज फंड को लांच किया। देश के शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे अर्बन चैलेंज फंड के जरिये नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण और पीपीपी के जरिए संसाधन जुटाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, सीआ-रजीएसएस के माध्यम से छोटे शहरों को क्रेडिट गारंटी का सहारा मिलेगा, जिससे वे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी कर सकेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश, गुजरात और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और ओ-डिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता वाले इस फंड के माध्यम से केंद्र स-रकार 4 लाख करोड़ तक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह फंड पारंपरिक अनुदान प्रणाली से आगे बढ़कर निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण होगा। अब शहरों को केवल फंड देने के बजाय उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत, जवाबदेह और निवेश के लिए तैयार बनाना ही केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के शहर आज आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के केंद्र बन रहे हैं और विकसित भारत @2047 का सपना इन्हीं शहरों की मजबूती पर निर्भर करता है। यूसीएफ की खास बात यह है कि इसमें केंद्रीय सहायता परियोजना लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, जबकि कम से कम 50 प्रतिशत फंड म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए जुटाया जाएगा। इससे न केवल वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा बल्कि निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल आवंटन में से 90,000 करोड़ परियोजनाओं के लिए, 5,000 करोड़ परियोजना की तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए और 5,000 करोड़ क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। यूसीएफ कोष शहरों में परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जिनमें पुराने शहरों और बाजारों का पुनर्विकास, शहरी परिवहन और लास्ट-माइल कनेक्टि-विटी, गैर-मोटर चालित परिवहन, जल और स्वच्छता ढांचा तथा जलवायु-लचीला विकास शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल वही परियोजनाएं प्राथमिकता में होंगी जो स्केलेबल, प्रभावशाली और वित्तीय रूप से व्यवहार्य (बैंक योग्य) हों, ताकि उनका दीर्घकालिक असर दिखाई दे। शहरी स्थानीय निकायों को इस योजना का प्रमुख स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि निकायों को अपनी वित्तीय क्षमता मजबूत करने, सुधार लागू करने और बाजार आधारित फंडिंग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहरी चुनौती कोष वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथाला ने कहा कि भारत का शहरीकरण अब एक निर्णायक मोड़ पर है और यूसीएफ इस दिशा में सुधार-आधारित और परिणाम-उन्मुख ढांचा प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान एक ई-डायरेक्टरी लॉन्च की गई, जो शहरों को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और क्रे-डिट एजेंसियों से जोड़ने का काम करेगी।

साथ ही, केंद्र और राज्यों के बीच एमओयू तथा विभिन्न हितधारकों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए, जिससे एक मजबूत और समन्वित कार्यान्वयन तंत्र तैयार किया जा सके। यह महत्वाकांक्षी ह्यशहरी चुनौती कोषह्व वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य भारत के शहरों को नए आर्थिक विकास केंद्रों और भविष्य के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करना है। यह फंड बुनियादी ढांचे के निर्माण को वित्तीय स्थिरता और संस्थागत मजबूती के साथ जोड़ता है, और साथ ही परियोजनाओं की बैंक-योग्यता तथा वित्तीय अनुशासन पर भी विशेष बल देता है।

विज का बड़ा एक्शनः निजी बैंकों के साथ सरकारी लेनदेन पर रोक, गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कसेगा शिकंजा

चंडीगढ : सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की सैकड़ों करोड़ की राशि को लेकर आईडीएफसी, एयू स्मॉल और कोटक महिंद्रा बैंक में जमकर हुए खेल के मामले में जहां सूबे की नायब सैनी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले में आला अफसरों पर भी शिकंजा कसते हुए पूरा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है। वहीं हाल के दिनों में हुई घटनाओं और पैसे के गोलमाल को लेकर प्रदेश के श्रम और ऊर्जा, परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने सभी विभागों से जुड़े अफसरों निजी बैंकों के साथ में लेनदेन नहीं करने और एक करोड़ से ऊपर की राशि को लेकर उन्हें अवगत कराने के साथ ही विभागीय मुखिया अधिकारी को अवगत कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने अपने तीनों विभागों में साफ कर दिया है कि दिशा निदेर्शों के बाद भी अगर कोई लेनदेन हुआ, तो उसके जिम्मेदार अफसरों और कर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा। विज का कहना है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों से ही लेनदेन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा निजी बैंकों को अपनी सूची से बाहर भी कर दिया है, अब इस तरह के माहौल में विभागों को अपने पैसे को लेक ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय बैंकों के साथ में लेनदेन और ज्यादा बड़ी रकम एक करोड़ से ज्यादा होने की सूरत में मंत्री और विभाग के मुखिया को अवगत कराने को कहा है। बिना वजह निजी बैंकों में खाते खुलवाने पर भी नजर भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि बैंकों में सरकारी पैसे की बंदरबांट और एफडी के नाम पर धोखाधड़ी जैसे केस हो जाने के बाद में मंत्री ने बिना किसी ठोस कारण के निजी बैंकों में कई कई खाते खुलवाने वाले अफसरों और कर्मियों को भी चिन्हित करने के निर्देश मंत्री विज ने आला अफसरों को कर दिए हैं। विज ने कहा कि किसी मामले में मिलीभगत मिली और लापरवाही हुई, तो इस तरह के अफसर नपेंगे। सरकारी दफ्तरों पर सौर ऊर्जा और जिलों में उपायुक्तों को निर्देश हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य को बिजली की बेहतर से बेहतर आपूर्ति करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाने की मुहिम चलाई है। विज ने सभी जिलों में जिला उपायुक्तों और अन्य दफ्तरों में अनिवार्य तौर पर सौलर पैनल लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह से प्रदेश स्तर पर भी सौलर ऊर्जा का को लेकर फोकस करने को कहा है, कई विभागों ने इस मामले में पहल की है, लेकिन काफी विभागों की गति सुस्त है। आने वाले दिनों में विज इस बारे में बैठक लेकर विभागों में इस काम को तेजी लाने को लेकर अफसरों की बैठक लेंगे। हरियाणा को सोलर में नंबर एक बनाने की कवायद के तहत ही यह मुहिम तेज होने जा रही है।

कार्यालय नगर पंचायत जोया, जनपद अमरोहा

पत्रांक :- 860/न०प० जोया / 2026 | दिनांकः- 10.04.2026

अल्पकालीन कूटेशन सूचना

नगर पंचायत जोया द्वारा जनहित में टाउन फण्ड/राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण / मरम्मत कार्य कराये जाने प्रस्तावित है, जिसकी मोहर बन्द निविदा दिनांक 20.04.2026 को अपराहन 1:00 बजे तक प्राप्त करने के उपरान्त कार्यालय में महोदय के सक्षम खोली जायेंगी, अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी को निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र0 स0	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि	निविदा शुल्क	अर्नेस्ट मनी	कार्यविधि
01	मौ०-जाटव कालोनी वार्ड नं.01 में वीरसिंह के मकान से रामप्रकाश के मकान तक सीसी टाईलस का उच्चीकरण का कार्य व नाली मरम्मत कार्य	213700	180	2प्रति.टीडीएस / एनएससी/आरटीजीएस	01 माह
02	मौ०-जाटव कालोनी वार्ड नं.-01 में रामस्वरूप के मकान से सतीश के मकान तक सीसी रोड़/नाली मरम्मत कार्य	195600	120	2प्रति.टीडीएस / एनएससी/आरटीजीएस	01 माह
03	उपजिलाधिकारी सदर अमरोहा के आवास पर दिवार, गेट व फर्श में इण्टरलोकिंग बिछाने का कार्य	272700	180	2प्रति.टीडीएस / एनएससी/आरटीजीएस	01 माह
04	नगर पंचायत जोया (श्यामपुर) में वेट-वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के समीप वेस्ट टू एनर्जी के टीनशेड को ऊंचा करने का कार्य	404200	250	2प्रति.टीडीएस / एनएससी/आरटीजीएस	01 माह

अध्यक्ष
नगर पंचायत-जोया, जनपद अमरोहा

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत-जोया, जनपद अमरोहा

अप्रैल में फैमिली के साथ इन शानदार जगहों को बनाएं डेस्टिनेशन पॉइंट, हर पल रहेगा यादगार

अप्रैल साल का एक ऐसा महीना होता है, जब देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर पहुंच सकते हैं।

हर कोई परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। इसलिए जब भी लोगों को समय मिलता है, तो वह अपने परिवार के साथ पसंदीदा जगहों पर पहुंच जाते हैं। अप्रैल के महीने में कई लोग अपने परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए निकलते हैं। अप्रैल साल का एक ऐसा महीना होता है, जब देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण लोग फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर मौज-मस्ती का प्लान बनाते हैं। लेकिन लोग सही जगह का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर पहुंच सकते हैं।

मैक्लॉडगंज

अगर आप अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में फैमिली संग घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मैक्लॉडगंज आपके लिए परफेक्ट जगह है। यह हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन है। जोकि धर्मशाला से करीब 5 किमी दूर है।

अप्रैल में मैक्लॉडगंज का मौसम सुहावना रहता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ यहां पर यादगार पल बिता सकते हैं। आप मैक्लॉडगंज में फैमिली के साथ सेंट जॉन चर्च, नड्डी व्यू पॉइंट, भागसूनाग वाटरफॉल और डल झील जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं।

बेताब वैली

जब भी जम्मू-कश्मीर में घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले गुलमर्ग, श्रीनगर या फिर सोनमर्ग का नाम लेते हैं। लेकिन आप इन सभी से हसीन बेताब वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह वैली जम्मू-कश्मीर का वह छिपा हुआ खजाना है, जिसकी खूबसूरती देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे।

बेताब वैली में घास के मैदान, शांत और शुद्ध वातावरण और झील झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। वहीं बॉलीवुड की कई फिल्मों की यहां पर शूटिंग हो चुकी है। अप्रैल के महीने में यहां का तापमान एकदम सुहावना रहता है।

झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है दशम जलप्रपात

दशम जलप्रपात लगभग 44 मीटर (144 फीट) की ऊँचाई से गिरता है, जिससे यह झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में शामिल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और झरने की गूंज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 34 किलोमीटर दूर, तैमारा गाँव के समीप स्थित दशम जलप्रपात (Dassam Falls), राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है, जो सुवर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और झरने की गूंज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

जलप्रपात की विशेषताएँ

ऊँचाई: दशम जलप्रपात लगभग 44 मीटर (144 फीट) की ऊँचाई से गिरता है, जिससे यह झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में शामिल है।

नाम की उत्पत्ति : स्थानीय मुंडारी भाषा में फ्रदाशोंगफ्र का अर्थ होता है पानी का गिरना। समय के साथ यह शब्द दशम में परिवर्तित हो गया।

प्राकृतिक संरचना: यह जलप्रपात एक निक पॉइंट का उदाहरण है, जहाँ नदी की ढलान में अचानक परिवर्तन होता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है।

दृश्य सौंदर्य : जलप्रपात के चारों ओर घने जंगल और चट्टानी क्षेत्र हैं, जो इसे पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं।

कैसे पहुँचें

सड़क मार्ग : रांची से दशम जलप्रपात तक पहुँचने के लिए NH-33 (अब NH-18) का उपयोग किया जा सकता है। अंतिम 10 किलोमीटर की यात्रा गाँव की सड़कों से होती है, जो संकरी लेकिन ड्राइविंग के लिए उपयुक्त हैं।

रेल मार्ग : निकटतम रेलवे स्टेशन रांची है, जहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से जलप्रपात तक पहुँचा जा सकता है।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

मानसून (जुलाई से सितंबर)- इस अवधि में जलप्रपात अपने पूर्ण प्रवाह में होता है, लेकिन भारी वर्षा के कारण फिसलन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हो सकती हैं।

शीतकाल (अक्टूबर से फरवरी) : इस समय मौसम सुखद होता है और भीड़ भी कम होती है, जिससे यात्रा अधिक आनंददायक होती है।

सुरक्षा सुझाव

जलप्रपात के नीचे तैराकी या स्नान से बचें, क्योंकि यहाँ की जलधारा तेज होती है और कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।

फिसलन से बचने के लिए उपयुक्त जूते पहनें और बच्चों पर विशेष ध्यान दें।

अपने साथ पानी और हल्का नाश्ता रखें, क्योंकि आसपास सीमित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त जानकारी

प्रवेश शुल्क : नि :शुल्क

पार्किंग: पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ 30 का शुल्क लिया जाता है।

सीढ़ियाँ: जलप्रपात के तल तक पहुँचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, जो अच्छी तरह से निर्मित हैं।

दशम जलप्रपात, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए, बल्कि फोटोग्राफरों और शांत वातावरण की तलाश करने वालों के लिए भी एक आदर्श गंतव्य है। यदि आप झारखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो दशम जलप्रपात को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें।

केरल के मुनरो आइलैंड की खूबसूरती देखकर झूम उठेंगे आप, प्रकृति प्रेमियों के लिए है जन्नत

जब भी केरल घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले एलेप्पी, कुमारकोम, मुन्नार, वायनाड, वागामों और त्रिशूर जैसी फेमस जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुनरो द्वीप के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।

दक्षिण भारत में जब किसी खूबसूरत राज्य में घूमने की बात होती है, तो बहुत सारे लोग केरल का नाम सबसे पहले लेते हैं। केरल दक्षिण भारत का पर्यटन हब माना जाता है। केरल की खूबसूरती हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां पर स्थित लैगून और बैकवॉटर देखने के लिए लोग केरल पहुंचते हैं। जब भी केरल घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले एलेप्पी, कुमारकोम, मुन्नार, वायनाड, वागामों और त्रिशूर जैसी फेमस जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुनरो द्वीप के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मुनरो द्वीप की खूबसूरती, खासियत और यहां पर मौजूद कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मुनरो द्वीप

केरल के कोल्लम जिले में स्थित मुनरो द्वीप एक अद्भुत और अनोखी जगह है। यह कोल्लम शहर के कुछ किमी की दूरी है। इस द्वीप को कई लोग मुंद्रोथुरुथु के नाम से भी जानते हैं।

केरल में अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर यह द्वीप स्थित है। मुनरो द्वीप राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 90 किमी की दूरी पर है। यह द्वीप एलेप्पी से करीब 87 किमी दूर और कोट्टयम से महज 84 किमी दूर है।

मुनरो द्वीप का इतिहास

मुनरो द्वीप का इतिहास काफी रोचक है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम पूर्व ब्रिटिश निवासी कर्नल मुनरो के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि जब कर्नल मुनरो ने देखा कि सिंचाई के लिए आसपास के इलाकों में बहुत समस्या हो रही है, तब इस द्वीप का निर्माण करवाया गया था।

मुनरो द्वीप की खासियत

केरल के साथ-साथ दक्षिण भारत का भी यह एक ऐसा आइलैंड है, जो नदी और झील के किनारे स्थित है। मुनरो द्वीप अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर स्थित है। जोकि अपने आप में अनोखा है।

इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह केरल का छिपा हुआ मोती है, जो करीब 8 द्वीपों से बना हुआ है। यहां पर स्थित बैकवाटर और लैगून पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

सैलानियों के लिए है खास

मुनरो द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर जो सैलानी बैकवाटर और लैगून से प्रेम करते हैं, उनके लिए मुनरो द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह खास जगह है।

मुनरो द्वीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांत और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पर कई पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। मानसून में इस द्वीप की खूबसूरती चरम पर होती है।

आसपास घूमने की जगहें

मुनरो द्वीप के आसपास कई शानदार और मनमोहक जगहें हैं। ऐसे में आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहां पर अष्टमुडी झील, वेस्ट एंड ईस्ट कल्लाडा और थेवलक्करा गांव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कैसे पहुंचे मुनरो द्वीप

बता दें कि मुनरो द्वीप पहुंचना आसान है। इसके पास में कोल्लम रेलवे स्टेशन है, जोकि यहां से 27 किमी दूर है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पास त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जोकि 80 किमी दूर है। ऐसे में आप एयरपोर्ट से कैब या टैक्सी करके मुनरो द्वीप जा सकते हैं।

महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना है कोयनानगर, मानसून में यहां घूमना है जन्नत के बराबर

कोयनानगर को महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोयनानगर की खासियत, यहां की खूबसूरती और यहां पर मौजूद शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

देश के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र एक प्रमुख राज्य होने के साथ ही खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यह एक ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर अरब सागर से घिरा है। महाराष्ट्र अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों के अपनी ओर आकर्षित करता है। महाराष्ट्र में कई ऐसी हसीन, ऐतिहासिक और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर लोनावाला, खंडाला और माथेरान जैसी जगहों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन यहां पर स्थित कोयनानगर के बारे में कम लोग जानते हैं। इस जगह को महाराष्ट्र का छिरा हुआ खजाना माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोयनानगर की खासियत, यहां की खूबसूरती और यहां पर मौजूद शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में कोयनानगर

कोयनानगर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। सतारा जिला खूबसूरत पहाड़ और झील-झरनों के लिए जाना जाता है। वहीं कोयनानगर को कोयना के नाम से भी जाना जाता है।

सतारा जिले में कोयना नदी के किनारे कोयनानगर है। यह सतारा शहर से कुछ ही दूरी पर बसा है। कोयनानगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 294 किमी दूर है। पूणे से 190 किमी और सांगली से 130 किमी दूर है।

कोयनानगर की खासियत

कोयनानगर चिपलून-सांगली राजमार्ग पर स्थित है और यह कई चीजों के लिए फेमस माना जाता है। कोयनानगर में स्थित कोयना बांधा भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक माना जाता है।

कोयना बांध के पीछे स्थित शिवसागर जलाशय भी कोयनानगर को खास बनाने का काम करता है। यह जगह सतारा जिले के साथ ही पूरे महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। यहां पर आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं।

कोयनानगर की खूबसूरती

बता दें कि कोयनानगर को खूबसूरती का खजाना माना जाता है। यह जगह शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपने शांत और शुद्ध वातावरण के लिए भी जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। कोयनानगर की हरियाली यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है।

यहां पर क्रिस्टल क्लियर झील, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और घने जंगल देखने को मिलेंगे। वहीं वीकेंड पर कई पर्यटक यहां पर पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। वहीं मानसून में कोयनानगर की खूबसूरती देखने लायक होती है।

कोयनानगर में घूमने की जगहें

कोयनानगर में कई शानदार और बेहतरीन जगहें हैं, जहां पर घूमने के बाद आप महाराष्ट्र की फेमस जगहों को भूल जाएंगे। यहां पर कोयना डैम, कोयना नदी, नेहरु गार्डन और कोयनानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि खूबसूरत जगहें मौजूद हैं।

कोयनानगर के आसपास कामरगांव, हूंबर्ली, वजेगांव, ओज़ार्डे वॉटरफॉल और कोयना बैकवाटर व्यू पॉइंट जैसी जगहों को घूम सकते हैं।

कैसे पहुंचे कोयनानगर

यहां पर पहुंचना बहुत आसान है, कोयनानगर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे है। जोकि करीब 192 किमी दूर है। वहीं कोयनानगर का नजदीकी रेलवे स्टेशन चिपलून है जो 42 किमी दूर है। पुणे से चिपलून के लिए लोकल ट्रेन आदि चलती हैं और यह शानदार जगह चिपलून-सांगली राजमार्ग पर स्थित है।

आमिर खान प्रोडक्शंस की 'एक दिन' से साई पल्लवी कर रही हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू, परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा रॉ केमिस्ट्री' और इमोशंस का जादू

साई पल्लवी की हिंदी डेब्यू फिल्म एक दिन में देखने मिलेगी उनकी इमोशनल डेप्थ और रॉ केमिस्ट्री की झलक

जब से साई पल्लवी और जुनैद खान स्टारर एक दिन का ट्रेलर और गाने रिलीज़ हुए हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म ने जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है।
अरिजीत सिंह की रूहानी आवाज़ ने फिल्म के संगीत में जो जान फूंकी है, उसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
आमिर खान प्रोडक्शंस की एक दिन, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान नज़र आने वाले हैं, एक प्यारी, जादुई और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करती है जिसने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। अपने दिलचस्प ट्रेलर और सुकून देने वाले संगीत के साथ, फिल्म ने उत्साह को और बढ़ा दिया है, जो रोमांस का एक ऐसा ताज़ा अंदाज़ पेश करती है जिसे कई लोग बड़े पर्दे पर मिस कर रहे थे।
फैंस विशेष रूप से साई पल्लवी को एक दिन के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखते देखने के लिए उत्साहित हैं। रिलीज़ से पहले, इंडस्ट्री के एक सूत्र ने स्क्रिप्ट पर साई के रिएक्शन और फिल्म की गहरी केमिस्ट्री और इमोशनल गहराई के बारे में खुलासा किया है।
इंडस्ट्री के सूत्र ने बताया, 'जब से साई ने एक दिन की स्क्रिप्ट सुनी, उनका रिएक्शन तुरंत 'हाँ' था, वह पूरी तरह से इसकी ओर खिंची चली आईं। वह फिल्म की रॉ केमिस्ट्री और इमोशनल गहराई से गहराई से जुड़ गईं, और उन्हें लगा कि यह एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में सबसे अलग है!'
ट्रेलर में उनके किरदार की झलक देखने को मिली, जिसमें साई पल्लवी, जुनैद के किरदार के विपरीत काफी शांत और आत्मविश्वासी नज़र आ रही हैं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और नैचुरल परफॉर्मेंस साफ तौर पर बताती है कि वह क्यों साउथ की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं और अब हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ रही हैं।
एक दिन एक लंबे अंतराल के बाद आमिर खान और फिल्म निर्माता मंसूर खान को फिर से साथ लाती है, जो हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा क्रिएटिव जोड़ियों में से एक है। साथ मिलकर, उन्होंने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं। एक दिन के साथ, यह जोड़ी रोमांस जॉनर में वापसी कर रही है, जिससे फैंस के बीच नया उत्साह पैदा हो गया है। उनके एक बार फिर साथ आने ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और दर्शक उस जादू को बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब हैं।
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी एक दिन में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और निर्माण आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा किया गया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

साउथ में मिले प्यार पर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने की बात

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपने करियर और आगामी प्रोजेक्ट पर बात की। इसी के साथ उन्होंने उन खास अवसरों को लेकर भी चर्चा की, जो हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को मिले हैं। बातचीत में तमन्ना ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर खुशी जाहिर की और कहा, 'मैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स के एक-एक करके रिलीज होने को लेकर बेहद खुश हूं'।

तमन्ना भाटिया ने इंडस्ट्री में खुद को मिलने वाले काम के मौकों के प्रति खुशी जताई। साथ ही कहा कि अधिकांश सितारों को ऐसे मौके नहीं मिलते, खासकर महिलाओं को। तमन्ना ने कहा, 'यह बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर कलाकारों को और शायद खासकर महिला कलाकारों को इस तरह का मौका नहीं मिलता। मेरे करियर को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रही हूं'।
अभिनेत्री ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिले बेशुमार प्यार और स्वीकार्यता पर अपनी बेहद खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'एक एक्टर के तौर पर मुझे भी इसमें एक ताजगी का एहसास होता है। और, मुझे लगता है कि दर्शक भी लगातार मेरे प्रति बहुत प्यार और अपनापन दिखा रहे हैं। उन्होंने मुझे सचमुच बहुत ही प्यार से अपनाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत के साउथ में मुझे बहुत ज्यादा स्वीकार्यता मिली है'।

तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म

तमन्ना ने आगे कहा, 'भारत के बाकी सभी हिस्सों से भी मुझे जिस तरह का प्यार और अपनापन मिल रहा है, वह मेरे लिए सचमुच रोमांचक है। साथ ही बहुत विनम्र कर देने वाला अनुभव है। और इसलिए, मैं लगातार ऐसे तरीके ढूंढ रही हूं, जिनसे मैं इस प्यार को किसी न किसी रूप में वापस लौटा सकूं'। वर्क फ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार की फिल्म 'वीवन' में नजर आएंगी। एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं। यह फिल्म इस साल रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

आदिवी शेष ने की अपनी को-एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की तारीफ

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर तेलुगु-हिंदी फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ आदिवी शेष प्रमुख भूमिका में हैं। अब आदिवी शेष ने मृणाल की जमकर तारीफ की है और उन्हें फिल्म के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक बताया है। हालांकि, मृणाल की फिल्म में एंट्री एक अन्य एक्ट्रेस के फिल्म से बाहर होने के बाद हुई है।
बातचीत के दौरान आदिवी शेष ने मृणाल ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने आज तक जितने भी लोगों से मुलाकात की है, उनमें से वह सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई हैं। जब भी हम सीन पर चर्चा करते थे, वह सचमुच जमीन पर बैठ जाती थीं। वह एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री हैं और मुझे लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया, वह कमाल का था। उनकी आंखों में जो सहानुभूति और भाव झलकते हैं, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्क्रीन पर उन्हें देखते ही लोगों के साथ एक झटपट जुड़ाव महसूस होता है।
शूटिंग के शुरुआती दिनों को याद करते हुए आदिवी शेष ने कहा कि पहले कुछ दिनों तक मृणाल हर दिन अलग मूड में सेट पर आती थीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दिन वह खुश और चुलबुली होती थीं और अगले ही दिन गंभीर हो जाती थीं। हालांकि, तीसरे दिन मुझे एहसास हुआ कि वह बस सीन के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही थीं। वह सेट पर आने से पहले ही तैयारी कर रही थीं और वास्तव में उस किरदार के मूड में ढल रही थीं, जिसे वह निभाने वाली थीं।

जेलर 2 से क्यों अलग हुए शाहरुख खान

शाहरुख खान और रजनीकांत, दोनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच खबर आई कि शाहरुख खान और रजनीकांत पर्दे पर एक-साथ नजर आ सकते हैं। खबरें थीं कि शाहरुख खान फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो करने वाले थे। हालांकि ताजा अपडेट में पता चला है कि शाहरुख खान ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। अब अभिनेता अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' पर ध्यान देना चाहते हैं। 'जेलर 2' के मेकर्स ने खान से एक कैमियो रोल के लिए संपर्क किया था। इसकी शूटिंग में लगभग 5 दिन लगते। शुरू में एक्टर इसके लिए तैयार थे। हालांकि, खान ने अपने ऑनस्क्रीन प्रेजेंस की खासियत बनाए रखने के लिए इसे मना कर दिया। बताया जाता है कि खान ने खुद रजनीकांत से बात की और भविष्य के किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की।

'किंग' के लिए खास लुक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान ने गुजारिश की थी कि 'जेलर 2' की रिलीज 'किंग' के बाद रखी जाए। इसकी वजह यह थी कि वह चाहते थे कि उनका अपीयरेंस सिर्फ उसी फिल्म के लिए खास रहे। 'किंग' में उनका एक खास लुक है। वह नहीं चाहते कि उससे पहले किसी और फिल्म में उनका वैसा ही लुक हो। 'जेलर 2' के मेकर्स ने इसे अगस्त में रिलीज करने का प्लान बनाया था।

मेकर्स कैमियो पर कर रहे विचार

मेकर्स अब कैमियो रोल के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में, मेकर्स ने घोषणा की थी कि फिल्म लगभग पूरी होने वाली है और यह प्रोजेक्ट अपने पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। शाहरुख खान की 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इसके निर्देशक सिद्धार्थ आनंद हैं। इसमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अरशद वारसी जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी होंगी।

विक्रांत मैसी ने किया खुलासा क्यों लिया था फिल्मों से ब्रेक

एक्टर विक्रांत मैसी ने दिसंबर 2024 में अपने फैंस को चौंका दिया था, जब उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया। इसके बाद इंडस्ट्री के प्रेशर और नेपोटिज्म को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं। लेकिन अब विक्रांत ने साफ किया है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया था। विक्रांत ने अपनी पत्नी शीतल ठाकुर के साथ परिणीति चोपड़ा के शो 'मॉम टॉक्स' में पैरेंटहुड के अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि वर्धान के जन्म के समय उनका काम बहुत ज्यादा था, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए थे। इसी वजह से उन्होंने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं कि हम खुद को इमोशनल, शारीरिक और मानसिक रूप से कितना देते हैं। एक नए पिता के तौर पर मेरा ध्यान हमेशा घर पर ही रहता था। मैंने ये तक नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं। मैं बस अपने काम जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि वर्धान और शीतल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूं।'

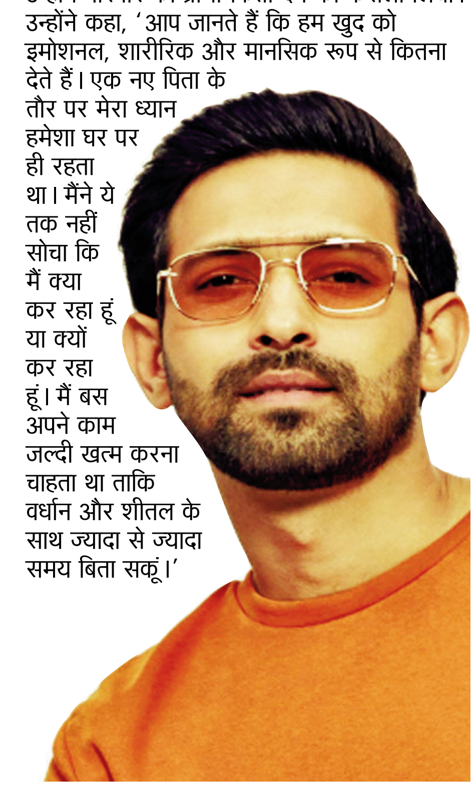

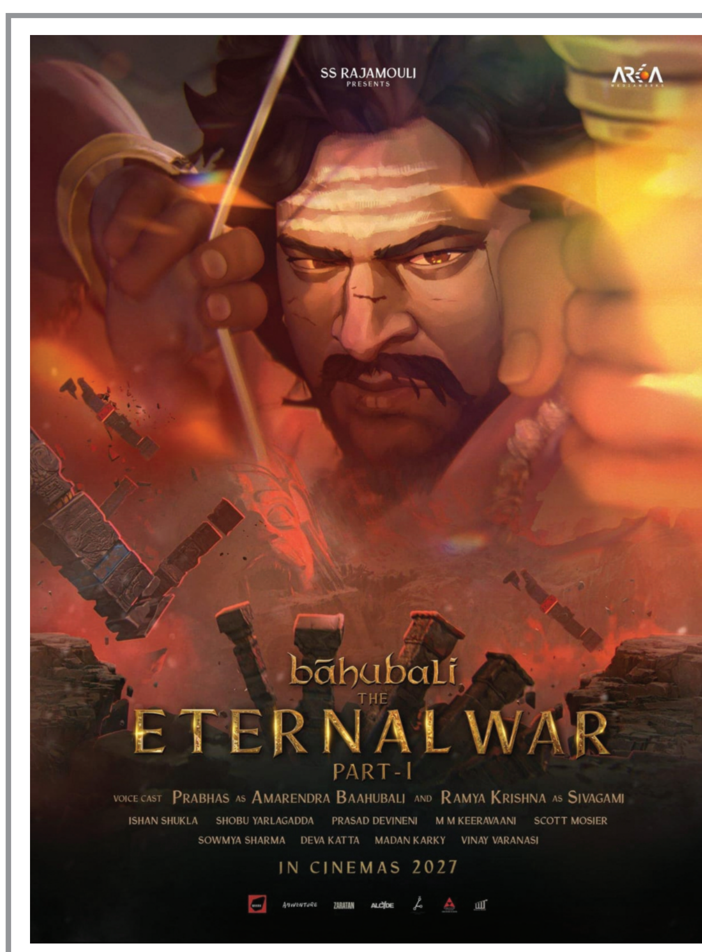

भारतीय सिनेमा का गर्व: 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का एनेसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ सिलेक्शन

बाहुबली फैंचाइज़ी, जिसमें 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली: द कंक्लूजन' जैसी दो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय सामग्री में से एक है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। जहाँ थिएटरों में इसने रिकॉर्ड तोड़े और नए बेंचमार्क सेट किए, वहीं अब मेकर्स इसे 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के साथ एक नए लेवल पर ले गए हैं, जिसके टीज़र ने ही ग्लोबल लेवल पर लहर पैदा कर दी है। अब एक और बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट डालते हुए, इस फिल्म को प्रतिष्ठित एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है।
'बाहुबली: द इटरनल वॉर' अपनी रिलीज से काफी पहले ही दुनिया भर में चर्चा बटोर रही है। एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के 'वर्क इन प्रोग्रेस' (Work in Progress) सेगमेंट में चुने जाने के साथ, यह फिल्म उन चुनिंदा भारतीय एनिमेशन फिल्मों में शामिल हो गई है जिन्हें इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। खास बात यह है कि 'स्पाइडर-वर्स' और 2025 में बेस्ट एनिमेशन का ऑस्कर जीतने वाली फिल्म 'फ्लो' (Flow) भी इसी सेगमेंट का हिस्सा रह चुकी हैं, जो बाहुबली फैंचाइज़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के मेकर्स ने जो टॉप-नॉच क्वालिटी और टेक्निकल बारीकियां हासिल की हैं, वे टीज़र में ही साफ़ नज़र आ रही थीं। इसके साथ ही, इस फैंचाइज़ी ने निश्चित रूप से भारतीय एनिमेशन सिनेमा के स्तर को ऊपर उठाया है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी है।
एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल हर साल जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस के एनेसी शहर में होता है। यह अलग-अलग तकनीकों (ट्रेडिशनल, कट-आउट, क्लेमेशन, CGI, आदि) से बनी एनिमेटेड फिल्मों के बीच एक कॉम्पिटिशन है। फेस्टिवल के दौरान, शहर के सिनेमाघरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा, शहर के केंद्र में झील और पहाड़ों के बीच 'पाक्वियर' (Pâquier) पर एक ओपन-एयर नाइट प्रोजेक्शन भी आयोजित किया जाता है। फेस्टिवल के टॉपिक के हिसाब से विशाल स्क्रीन पर क्लासिक या हालिया फिल्में दिखाई जाती हैं। शनिवार शाम को सभी पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है।
'बाहुबली: द इटरनल वॉर' दो भागों वाला एक एनिमेटेड महाकाव्य है, जिसका निर्देशन पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ईशान शुक्ला ने किया है। पार्ट 1 का टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है और फिल्म 2027 में रिलीज़ होने वाली है।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।